घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 23, अंक - 13- रविवार 15- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने के प्रस्ताव पर एनसीपी-एसपी सहमत

सुप्रिया सुले बोलीं...हर राज्य में बराबर सीटें बढ़ेंगी तो समर्थन देंगे,महिला आरक्षण भी लागू हो...

मुंबई,14 नवम्बर 2026। शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाने के भाजपा के प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है। इसके साथ ही महिला आरक्षण लागू करने की भी बात कही गई है। सुले ने बताया कि भाजपा ने परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं को बैठक में बुलाया था। बैठक में भाजपा ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि,सुले ने स्पष्ट किया कि एनसीपी-एसपी ने विधेयक का समर्थन करने का अभी औपचारिक फैसला नहीं लिया है। पार्टी को प्रस्तावित विधेयक की आधिकारिक कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ भी चर्चा करना चाहती है। अगर सभी दल सहमत होते हैं, तो एनसीपी-एसपी इसका समर्थन करने के लिए तैयार है। सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों विधेयकों को पारित होते देखना चाहती है। इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना जरूरी है। उन्होंने लोकसभा सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि छोटे निर्वाचन क्षेत्र होने से सांसदों के लिए मतदाताओं तक पहुंचना आसान होगा। इससे प्रशासन और विकास कार्यों को भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। सुप्रिया सुले ने अपने बारामती लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यहां मतदाताओं की संख्या पहले करीब 10-12 लाख थी,जो अब बढ़कर लगभग 20-22 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र के हर गांव और इलाके तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। सांसद निधि के सिर्फ 5 करोड़ रुपए से हर क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना भी संभव नहीं है। सुले के मुताबिक,प्रभावी प्रशासन और विकास के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा जरूरी है।



जनकपुरधाम और अयोध्या के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन,रेलवे ने दी मंजूरी

नई दिल्ली,14 नवंबर 2026। भारतीय रेलवे ने भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जनकपुरधाम और अयोध्या के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दी है। करीब 604 किलोमीटर लंबी यह रेल सेवा दोनों देशों के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को आपस में जोड़ेगी। रेलवे के अनुसार,यह ट्रेन नेपाल स्थित जनकपुरधाम से उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट तक चलेगी। इसके रास्ते में बिहार और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहर और कस्बे आएंगे। ट्रेन का वाणिज्यिक ठहराव जयनगर, मधुबनी,शीशो,सीतामढ़ी,रक्सौल,नरकटियागंज,गोरखपुर,बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम में होगा। इसके अलावा ट्रेन अपने दोनों शुरुआती और अंतिम स्टेशनों पर भी रुकेगी। यह साप्ताहिक ट्रेन जनकपुरधाम से प्रत्येक शनिवार और अयोध्या कैंट से प्रत्येक सोमवार को रवाना होगी। इस रेल सेवा से नेपाल के जनकपुरधाम और भारत के अयोध्या के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जनकपुरधाम को माता सीता की जन्मस्थली और अयोध्या को भगवान श्रीराम की जन्मस्थली माना जाता है। ऐसे में यह ट्रेन रामायण से जुड़े धार्मिक स्थलों के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवागमन को सुविधाजनक बनाएगी।

2014 में विपक्ष सदमे में था...चुनाव में पहले कड़े मुकाबले और गठबंधन होते थे,अब लोकतंत्र खत्म कर दिया : राहुल गांधी



हैदराबाद,14 नवम्बर 2026। राहुल गांधी ने शनिवार को हैदराबाद में कहा कि 2014 में हमने एक बिल्कुल नया चुनाव देखा। कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। राजनीतिक व्यवस्था में भारी मात्रा में पैसा झोंक दिया गया।

चुनावी व्यवस्था,जिसमें अक्सर कड़े मुकाबले और गठबंधन देखने को मिलते थे,वह अचानक पूरी तरह बदल गई। विपक्ष सदमे में था तो यह कहना गलत नहीं होगा। राहुल हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के भारत समिट के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम हैदराबाद के नोवोटेल होटल में आयोजित किया गया। राहुल गांधी ने कहा...फासीवादी अक्सर चिल्लाते हैं। वे शोर मचाते हैं, चीखते-चिल्लाते हैं और किसी की सुनते नहीं। चूंकि आम लोग दूसरों की बात सुनते हैं, ध्यान देते हैं और विनम्र होते हैं, इसलिए फासीवादियों की आवाज ज्यादा तेज सुनाई देती

हम वर्तमान के साथ भविष्य के लिए लड़ रहे : राहुल

हम केवल वर्तमान से नहीं लड़ रहे, हम वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारा इतिहास महात्मा गांधी से शुरू से हुआ था। हमारे दो हथियार हैं- सत्य और अहिंसा। हमने देखा है कि हिंसा काम नहीं करती, दया काम करती है। लोगों को समझाना काम करता है।

कुछ लोगों को लगता,वे सब जानते : राहुल

आपको कई लोग व्यवसायों के शीर्ष पर मिल जाएंगे। वे शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं और राजनीति में हम उन्हें 'फासीवादी' कहते हैं।

राहुल गांधी हैदराबाद में गिग वर्कर्स की बाइक रैली में हुए शामिल

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल हुए। यह रैली 'तेलंगाना गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना' के शुभारंभ से पहले निकाली गई। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। रैली शिल्पाराम्म सभागार से शुरू होकर शहर के आईटी कॉरिडोर स्थित माधापुर के जयभेरी ग्राउंड में समाप्त हुई। इस दौरान राहुल गांधी बाइक पर पीछे बैठे नजर आए और गिग वर्कर्स के साथ रैली में शामिल हुए। योजना के शुभारंभ के अवसर पर गिग वर्कर्स को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार उनकी समस्याओं और चिंताओं को दूर करने के अपने वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा, तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ मेरी एक बैठक हुई थी। उस दौरान आपने अपना दुख और दर्द साझा किया था। मैंने आपसे वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री और हम सभी आपकी मांगों पर कदम उठाएंगे। आपकी मदद और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।



ओडिशा हाईकोर्ट में जजों के 60% पद खाली

1.70 लाख मुकदमे लंबित,बीजद सांसद सस्मित ने कानून मंत्री को लिखा पत्र

भुवनेश्वर,14 नवम्बर 2026। ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की भारी कमी का मुद्दा सामने आया है। अदालत में स्वीकृत पदों के मुकाबले 60 फीसदी से ज्यादा पद खाली हैं। इसका असर मुकदमों की सुनवाई पर पड़ रहा है और हजारों मामले वर्षों से लंबित हैं। इस स्थिति को लेकर बीजू जनता दल (बीजद) के राज्यसभा सांसद डॉ. सस्मित पात्रा ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर तत्काल नियुक्तियां करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक पदों को भरने में देरी से ओडिशा में लोगों को समय पर न्याय मिलने में परेशानी हो रही है। 14 नवंबर 2026 को लिखे पत्र में सांसद ने बताया कि ओडिशा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 33 हैं। फिलहाल अदालत में 13 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन 15 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके रिटायर होने के बाद अदालत में केवल 13 न्यायाधीश ही रह जाएंगे। यानी 33 पदों में से 20 खाली होंगे। यह करीब 60.6 प्रतिशत पदों की कमी है। सांसद के मुताबिक, यह राष्ट्रीय स्तर पर हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के औसत रिक्त पदों की दर करीब 26 प्रतिशत से दोगुने से भी अधिक है।सस्मित पात्रा ने पत्र में बताया कि पिछले एक साल में ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या लगातार कम हुई है।



पंजाब के तरनतारन में तीर्थयात्रियों की 2 बसों की टक्कर में 5 की मौत,21 घायल

तरनतारन,14 नवम्बर 2026। पंजाब के तरनतारन में शनिवार को नेशनल हाईवे-54 पर तीर्थयात्रियों से भरी दो बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोनों बसें तीर्थ यात्रा स्कीम के तहत यात्रियों को लेकर जा रही थीं। इनमें करीब 80 लोग सवार थे। एक बस के श्रद्धालु अमृतसर के गोल्डन टेंपल में माथा टेककर लौट रहे थे। जबकी दूसरी बस हरिके से अमृतसर जा रही थी। इसी दौरान नौशहरा पन्नूआं के पास मोटरसाइकिल सवारों को बचाने की कोशिश में एक बस का संतुलन बिगड़ गया। बस डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ पहुंच गई और सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।



मोटरसाइकिल को बचाने में हुआ हादसा

शुरुआती जानकारी के अनुसार,शाम करीब 4 बजे एक बस के सामने अचानक मोटरसाइकिल सवार आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में ड्राइवर बस पर नियंत्रण खो बैठा। बस डिवाइडर पार करते हुए दूसरी तरफ चली गई, जहां सामने से आ रही दूसरी बस से उसकी सीधी टक्कर हो गई।

लोग बोले...ऐसा लगा जैसे कोई धमाका हुआ : बता दें कि एक बस फिरोजपुर से श्रद्धालुओं को लेकर अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल के दर्शन करवाने गई थीं। लौटते वक्त नौशहरा पन्नूआं के पास हादसा हो गया। इसमें 37 लोग सवार थे। वहीं, दूसरी बस हरिके से अमृतसर जा रही थी, इसमें करीब 50 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों की टक्कर होते ही धमाके जैसी आवाज सुनाई दी।

टक्कर के बाद बसों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त

आमने-सामने की टक्कर में दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बसों में बैठे यात्रियों को चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और बसों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए।

सौरभ के इनपुट पर 33 ठिकानों पर सीबीआई रेड

6 राज्यों में छापे,लाइव सट्टा पैनल मिले,किराए के खातों से विदेश भेजते थे रकम

रायपुर,14 नवम्बर 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी कर सट्टा पैनल चलाने वाले ऑपरेटरों के नेटवर्क का पता लगाया। छापेमारी के दौरान कई जगह लाइव सट्टा और जुए के पैनल चलते मिले। सीबीआई ने इन्हें मौके पर ही बंद कराया। कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और कई दस्तावेज जब्त किए गए। इनसे पता चला कि दूसरे लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर सट्टे की रकम जमा की जाती थी। इसके बाद हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजा जाता था। सीबीआई के मुताबिक,यह कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर की गई। उसे 1 नवंबर 2026 को ओमान से भारत लाया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर रायपुर की विशेष अदालत से 8 दिन की पुलिस रिमांड ली थी। पूछताछ में ऐप चलाने के तरीके और देशभर में फैले पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क की जानकारी मिली। यहां 'प्रत्यर्पित' की जगह 'ओमान से भारत लाया गया' सरल और आम बोलचाल का विकल्प है।



इन शहरों में हुई छापेमारी

सीबीआई ने जिन शहरों में कार्रवाई की,उनमें छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग के अलावा अमृतसर,दिल्ली,नागौर,धौलपुर,भोपाल,इंदौर,अहमदाबाद,वडोदरा,सूरत,मुंबई और नागपुर शामिल हैं।

दूसरे लोगों के बैंक खातों में जमा होती थी सट्टे की रकम

जांच में सामने आया है कि महादेव ऐप का संचालन विदेश में बैठे लोगों के जरिए किया जाता था। इसका हेड ऑफिस विदेश में है और भारत में बड़े नेटवर्क के जरिए पैनल ऑपरेट किए जाते हैं। पैनल ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी बनाते थे और उनसे सट्टे की रकम वसूलते थे। इस रकम को ऐसे बैंक खातों में जमा किया जाता था, जो दूसरे लोगों के नाम पर खुलवाए गए थे या किराए पर लिए गए थे। इसके बाद मुनाफे की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजी जाती थी।

सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक जेल में : सीबीआई की 8 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सौरभ चंद्राकर को 12 नवंबर 2026 को रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। लेकिन शुक्रवार को ईडी ने उसे अरेस्ट कर 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पर लिया है। सीबीआई ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले की जांच एजेंसी को सौंपी थी। इसके बाद दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। अब जांच में विदेश में बैठे अन्य आरोपियों, सट्टा नेटवर्क चलाने में मदद करने वालों और संबंधित सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। फरार आरोपियों को भारत लाने के लिए दूसरे देशों से कानूनी प्रक्रिया भी जारी है।

बैंक खाता-सिम देने पर भी होगी कार्रवाई : एजेंसी ने लोगों को चेताया है कि ऑनलाइन सट्टा और जुआ गैरकानूनी हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को सट्टेबाजी के लिए अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान से जुड़े दस्तावेज देना भी अपराध है। ऐसा करने पर खाताधारक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

बड़ा झटका! आयुष्मान योजना से बाहर होंगी 112 बीमारियां,अब निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगा इलाज

रायपुर,14 नवम्बर 2026। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब निजी अस्पतालों में 112 प्रकार की बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए नहीं हो सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इन बीमारियों के पैकेज निजी अस्पतालों के लिए हटाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों के इलाज की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के अनुसार, निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना से 112 प्रकार के बीमारी पैकेज हटाए गए हैं। सरकारी अस्पतालों के लिए व्यवस्था यथावत रहेगी। पहले सरकारी अस्पतालों के लिए 23 पैकेज आरक्षित थे। अब इनमें 89 नए पैकेज जोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की कुल संख्या 112 हो गई है।



इन बीमारियों के इलाज पर पड़ेगा असर

निजी अस्पतालों के लिए हटाए गए पैकेज में कई सामान्य और गंभीर बीमारियों के उपचार शामिल हैं। इनमें मोतियाबिंद, फ्रैक्चर, लिवर संबंधी रोग, हाई रिस्क डिलीवरी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार प्रमुख हैं। इसके अलावा गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस और लिवर की कुछ बीमारियों के इलाज के पैकेज भी शामिल हैं। सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी जैसे उपचार भी इस सूची में हैं। इस बदलाव के बाद इन बीमारियों से पीड़ित मरीज निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त या क्लेम आधारित इलाज नहीं करा सकेंगे। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इनका उपचार आयुष्मान योजना के तहत जारी रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को इस नई व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए उपचार पैकेज की व्यवस्था में यह बदलाव प्रभावी होगा। आयुष्मान योजना में गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करने,जबरन इलाज करने,योजना के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने और फर्जी क्लेम जैसी शिकायतें सामने आई थीं। इसके साथ ही निगरानी तंत्र की कमजोरियां और धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने जैसी समस्याएं भी इस फैसले के पीछे वजह मानी जा रही हैं।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में भाजपा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 100 से अधिक लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ

कांकेर,14 नवम्बर 2026। आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच आज कांकेर जिले के नरहरपुर में कांग्रेस ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत शक्ति प्रदर्शन किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में भाजपा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भूपेश नेताम ने अपने 100 से अधिक समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। दरअसल, करीब 20 दिन पहले भूपेश नेताम ने भाजपा से इस्तीफा दिया था। अब दिसंबर माह में प्रस्तावित नगर पंचायत चुनाव से पहले उनका अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होना नरहरपुर की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सभी नए सदस्यों को गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया।

भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना : सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने धान खरीदी,कथित वोट चोरी, युवाओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे उठाए। बघेल ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर लोगों को न चना मिला और न ही शक्कर। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की अपील की।



आदिवासी और जनजाति में फर्क कर रही कांग्रेस...दोनों एक ही समाज, 50 साल केंद्र में रही कांग्रेस,लेकिन जनजातीय मंत्रालय नहीं बनाया : किरणदेव

रायपुर,14 नवम्बर 2026। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आदिवासी और जनजाति शब्द को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी और जनजाति दोनों एक ही समाज हैं,फिर इनके बीच फर्क क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस 50-55 साल तक केंद्र की सत्ता में रही, लेकिन उसने जनजाति समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय तक नहीं बनाया। किरणदेव ने यह बातें शनिवार को रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं।

कांग्रेस बताए, जनजाति समाज के लिए क्या किया? किरण सिंह देव ने कहा कि, बीजेपी सरकार जनजाति समाज के विकास और उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार की एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं इस समाज के विकास के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी शामिल है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि इतने लंबे समय तक केंद्र में सरकार रहने के बावजूद उसने जनजाति समाज के विकास के लिए क्या किया और कौन-सी योजनाएं शुरू कीं।



भाषा-बोली अलग,लेकिन समाज एक ही है : सिंहदेव ने आदिवासी और जनजाति शब्दों के बीच अंतर किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बस्तर में ही हर 20-25 किलोमीटर पर अलग-अलग जनजातीय समुदाय मिलते हैं। उनकी भाषा, बोली, खान-पान और पहनावा अलग-अलग हो सकता है,लेकिन सभी जनजाति समाज का हिस्सा हैं। ऐसे में आदिवासी और जनजाति को अलग-अलग बताकर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आदिवासी समाज के लोग भी जनजाति समाज में ही आते हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश और प्रदेश के जनजातीय नायकों का सम्मान किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से याद किया जाता है। इसी तरह बस्तर के गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे नायकों ने भी देश और समाज के लिए योगदान दिया है। इन वीरों के सम्मान और उनके योगदान को याद करने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

15 नवंबर को धरमजयगढ़ में कार्यक्रम : किरण सिंह देव ने बताया कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सरगुजा से लेकर जशपुर और आसपास के जनजातीय क्षेत्रों में उत्साह है। बड़ी संख्या में समाज के लोग इसमें शामिल होंगे।

संपादकीय

चीन पर निर्भरता घटाने की हो तैयारी

गत नौ नवंबर को चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एलान किया कि कुछ निर्यात प्रतिबंधों पर लगी अंतरिम रोक की अवधि दो महीने बढ़ाई जा रही है। यानी 10 जनवरी तक के लिए उसने निर्यात प्रतिबंध के निर्णय को टाल दिया है। इसका अर्थ है कि दुनिया भर के उद्योगों को दो महीने की तात्कालिक राहत मिल गई। जर्मनी,जापान एवं भारत के कारखानों से लेकर सामरिक तैयारियों में लगे तमाम देशों के लिए यह बयान किसी बड़ी रणनीतिक रियायत से कम नहीं। चीन का यह फैसला विश्व में वाहन निर्माण और रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों की किस्मत तय करने वाला था कि अगले दो महीनों तक वे सुचारु रूप से चलती रहेंगी या ठप पड़ जाएंगी?
रेयर अर्थ 17 धातुओं का एक समूह है। हालांकि नाम के अर्थ की कसौटी पर देखा जाए तो ये तत्व उतने दुर्लभ भी नहीं। इन्हें दुर्लभ बनाती है कि इन्हें पृथक करने और रिफाइनिंग यानी परिष्कृत करने की क्षमता। यह प्रक्रिया बेहद जटिल,प्रदूषणकारी और खर्चीली है। परिष्कृत रेयर अर्थ तत्वों का उपयोग छोटे,बेहद शक्तिशाली मैग्नेट या चुंबक बनाने में होता है। यही मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों,एयर टर्बाइनों,स्मार्टफोन,हार्ड ड्राइव,लड़ाकू विमानों और गाइडेड मिसाइलों के भीतर लगे होते हैं। इनकी महत्ता इससे समझी जा सकती कि अगर एक मामूली से वजन का मैग्नेट समय पर न पहुंचे तो वह बड़े से बड़े कारखाने की चाल को रोक सकता है। रेयर अर्थ की समूची आपूर्ति शृंखला पर चीन का पूरी तरह से वर्चस्व है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आइईए के अनुसार 2024 में मैग्नेट निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रेयर अर्थ खनिजों के खनन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत, परिष्कृत सामग्री में करीब 91 प्रतिशत और तैयार मैग्नेट के उत्पादन में लगभग 94 प्रतिशत थी। डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसी भारी दुर्लभ धातुओं के मामले में तो चीन की हिस्सेदारी लगभग शत प्रतिशत है। ये धातुएं मैग्नेट को उच्च तापमान पर भी प्रभावी एवं सक्षम बनाए रखती हैं। रेयर अर्थ भले ही भारत समेत कई देशों में हों,लेकिन परिशोधन के मामले में ऐसा नहीं है और यही सबसे बड़ा रणनीतिक अवरोध है। आखिर यह स्थिति बनी कैसे? अप्रैल 2025 में चीन ने कुछ चुनिंदा रेयर अर्थ खनिजों पर निर्यात नियंत्रण लागू करते हुए उनकी आपूर्ति के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। अक्टूबर 2025 में उसने इन पाबंदियों का दायरा अप्रत्याशित रूप से बढ़ाते हुए इसमें औद्योगिक उपयोग में काम आने वाले हीरे और लीथियम बैट्री तकनीक को भी शामिल कर लिया।

बिरसा मुंडा : क्रांतिकारी,समाज-सुधारक और जन-आस्था के हैं भगवान



ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

किसी महापुरुष का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाता कि उसने अपने समय में कितनी लोकप्रियता अर्जित की,बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि उसने अपने समाज की पीड़ा को कितनी गहराई से समझा, अन्याय के विरुद्ध कितनी निर्भीकता से खड़ा हुआ और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी चेतना छोड़ी। इस कसौटी पर बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के उन विलक्षण नायकों में दिखाई देते हैं,जिनका जीवन छोटा था, लेकिन संघर्ष विराट। मात्र लगभग 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य, जमींदारी शोषण,महाजनी व्यवस्था, सामाजिक कुरीतियों और सांस्कृतिक दासता के विरुद्ध ऐसी चेतना जगाई, जिसने उन्हें केवल आदिवासी नायक नहीं, बल्कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के अग्रणी जननायकों की पंक्ति में खड़ा कर दिया।आदिवासी अस्मिता,स्वतंत्रता-संग्राम,जल-जंगल-जमीन और आध्यात्मिक आस्था के प्रतीक ऊलगुलान यानी बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता की चेतना ने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें धरती आबा और बिरसा भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनका संघर्ष केवल अंग्रेजों से मुक्ति का नहीं, अस्मिता, स्वाभिमान और स्वराज का महासंग्राम था। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातु में जन्मे बिरसा मुंडा का जीवन उस भारत की कहानी है,जिसे औपनिवेशिक सत्ता केवल राजस्व और संसाधनों की दृष्टि से देखती थी।आदिवासी के लिए जंगल केवल जंगल नहीं था,जमीन केवल जमीन नहीं थी और नदी केवल पानी का स्रोत नहीं थी। वह उसकी जीवन-पद्धति,संस्कृति, आस्था और अस्तित्व का आधार थी। अंग्रेजी शासन और उससे जुड़ी जमींदारी-महाजनी व्यवस्था ने जब इस जीवन-दर्शन को चुनौती दी,तब बिरसा के भीतर विद्रोह जन्मा। यहीं बिरसा मुंडा के संघर्ष को देखने का एक नया दृष्टिकोण सामने आता है। उनका आंदोलन केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का राजनीतिक आंदोलन नहीं था। वह उससे कहीं अधिक व्यापक था। वह पूछ रहा था-किसका जंगल? किसकी जमीन? किसका शासन? किसकी संस्कृति? और किसके अधिकार? यही प्रश्न आगे चलकर उनके प्रसिद्ध'ऊलगुलान',अर्थात् महान जन विद्रोह,की आत्मा बने।

बिरसा ने महसूस किया कि किसी समाज को केवल बाहरी सत्ता नहीं गुलाम बनाती, उसके भीतर की कमजोरियां भी उसे कमजोर करती हैं। इसलिए उन्होंने तलवार से पहले चरित्र और चेतना को अपना हथियार बनाया। उन्होंने आदिवासी समाज में फैली अंधविश्वासपूर्ण प्रवृत्तियों,नशे,सामाजिक बुराइयों और रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को अपने धर्म,संस्कृति और

परंपराओं के प्रति जागरूक किया। हिंसा और नशे से दूर रहने,नैतिक जीवन जीने और सामूहिक एकता बनाए रखने की प्रेरणा दी। इस अर्थ में बिरसा केवल क्रांतिकारी नहीं थे,वे समाज के भीतर से समाज को बदलने वाले सुधारक भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि जिस समाज के भीतर आत्मविश्वास मर जाता है, वह बाहरी शोषण का प्रतिरोध लंबे समय तक नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने पहले आदिवासी समाज में आत्मसम्मान जगाया और फिर उसे अंग्रेजी सत्ता के सामने खड़ा किया। उनका संघर्ष किसानों और आदिवासियों के उस अधिकार के लिए था जिसे औपनिवेशिक व्यवस्था ने धीरे-धीरे छीन लिया था। महाजन कर्ज देते और बदले में जमीन पर कब्जा कर लेते। जमींदारी व्यवस्था शोषण को संस्थागत रूप देती। अंग्रेजी कानून आदिवासी जीवन-पद्धति के अनुकूल नहीं थे। बिरसा ने इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। उनके लिए स्वराज का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था,स्वराज का अर्थ था अपनी जमीन पर अपना अधिकार, अपनी संस्कृति पर अपना अधिकार और अपने जीवन पर अपना निर्णय।

यही कारण है कि बिरसा का 'ऊलगुलान' इतिहास में एक असाधारण घटना बन गया। 1895 से 1900 के बीच उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा। अंग्रेजी शासन ने उनके आंदोलन को अपने लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा। गिरफ्तारियां हुईं,दमन हुआ, गोलियां चलीं,लेकिन आंदोलन की चेतना को कैद नहीं किया जा सका। जनवरी 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी की घटना ने संघर्ष को और उग्र रूप दिया। अंततः बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार हुए और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने उनके शरीर को समाप्त किया,लेकिन बिरसा को इतिहास से मिटाने की अंग्रेजों की कोशिश विफल हो गई। लोकगीतों, कथाओं,स्मृतियों और आदिवासी चेतना में वे जीवित रहे। यही किसी महापुरुष की वास्तविक विजय होती है-जब व्यक्ति चला जाता है,लेकिन उसका विचार समाज की सामूहिक चेतना बन जाता है। और यहीं बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व का सबसे अद्भुत पक्ष सामने आता है-वे आदिवासी समाज के लिए केवल नायक नहीं रहे,'भगवान' बन गए। झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में उन्हें श्रद्धा से 'बिरसा भगवान' और 'धरती आबा' कहा जाता है। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है। इसके पीछे उस समाज की गहरी कृतज्ञता है,जिसने बिरसा में अपने अस्तित्व की रक्षा करने वाले मसीहा को देखा। जिस व्यक्ति ने उनकी धरती, संस्कृति, सम्मान और अधिकार के लिए अपना जीवन न्योछावर किया,वह उनके लिए देवतुल्य हो गया।

आज बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय स्मृति में जिस व्यापकता से प्रतिष्ठा मिली है,उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा को केवल आदिवासी समुदाय के नायक के रूप में नहीं,बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय अस्मिता के नायक के रूप में जन-जन तक पहुंचाया। 2021 में 15 नवंबर को'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा इसी राष्ट्रीय पुनर्स्मरण का महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। 2024 से 2025 तक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में जनजातीय गौरव वर्ष के कार्यक्रम हुए। 2024 में प्रधानमंत्री ने बिहार के जमुई में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया तथा जनजातीय क्षेत्रों के विकास से जुड़े अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की। 2025 में उनकी 150 वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के डेडियापाड़ा में फिर बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत की स्वतंत्रता,सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा में जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में रहा है।

बिरसा मुंडा : राष्ट्रीय चेतना का वनवासी स्वर



प्रमोद दीक्षित मलय
बांदा,उत्तरप्रदेश

वर्ष था 1898,और दिनांक थी 28 जनवरी। बंगाल प्रेसिडेंसी के रांची जेल के फाटक पर वनवासियों का समूह एकत्रित हो चुका था। वातावरण में ठिठुरन थी पर लोगों के तन-मन में उत्साह की गर्माहट समाई हुई थी।आंखों में अपने मार्गदर्शक से मिलने के लालसा एवं बेचैनी थी। उनकी नजरें जेल के मुख्य द्वार पर थीं कि तभी चरमराहट के साथ फाटक खुला और और एक किशोर वनवासी बाहर निकला। उपस्थित वनवासियों ने उसे कंधों पर उठा लिया। युवक ने मुट्ठी आकाश में उठा हुंकार भरी,अबुआ दिशुम, अबुआ राज (अपना देश, अपना राज)। भीड़ ने यह नारा दुहराया और उच्च स्वर से उद्घोष किया-बिरसा भगवान की जय,धरती आबा-बिरसा मुंडा। यह किशोर कोई और नहीं बल्कि वनवासियों के लिए भगवान बन चुका बिरसा मुंडा था,जिसे वनवासी समाज आदर से धरती आबा नाम से पुकार अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे थे। वनवासियों में राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाने वाले बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवम्बर को देश जनातीय गौरव दिवस के रूप में मना भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले वनवासी समाज के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उल्लेखनीय है कि बिरसा मुंडा को राजद्रोह के लिए आदिवासियों को प्रेरित करने के आरोप में 24 अगस्त, 1895 में गिरफ्तार 50 रुपये जुर्माना लगाया गया था। वह उस दिन दो साल के सश्रम कारावास से मुक्त हुए थे।

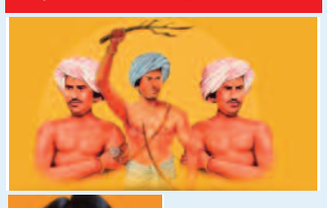
बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर,1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी अंतर्गत रांची जिले के उलिहातू गांव में (पाठांतर से चलकद गांव में) एक वनवासी परिवार में हुआ था,जो वर्तमान में झारखंड के खूंटी जनपद में है। पिता सुगना मुंडा एवं माता कर्मी मुंडा नवजात शिशु को देख फूले न समाए किंतु घर की दीवारों पर टंगी निर्धनता की चादर देख उदास हो गये। गरीबी और जमींदारों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार से वनवासी मुंडा समाज कराह रहा था। अंग्रेजी सत्ता जल, जंगल और जमीन के वनवासियों के सामूहिक हक खूंटीकट्टी को समाप्त कर धीरे-धीरे वनवासियों को बेदखल कर रही थी। प्राकृतिक संसाधनों की लूट चरम पर थी। अंग्रेजों के आधुनिक हथियार एवं सुसंगठित सैन्य दल के सम्मुख वनवासियों का विरोध कहां तक ठहरता जो परम्परागत हथियारों तीर-कमान,लाठी और बरछी पर आश्रित था। फलतःविरोध में उठा हर स्वर निर्दयतापूर्वक दबा दिया जाता। वनवासियों का सरल स्वभाव एवं अशिक्षित होना तथा नेतृत्व का अभाव भी बड़ा कारण था कि मुंड़ा और अन्य वनवासी समाज असंगठित एवं बिखरा हुआ था। ऐसे संकट के समय में बढ़ते हुए शिशु बिरसा मुंडा विद्यालय जाने की अवस्था पर पहुंचा तो पिता ने गांव सालगा में शिक्षक जयपाल नाग के हाथों में बिरसा को सौंप दिया। बालक बिरसा जीवन में जैसे कुछ अलग करने के लिए ही जन्मा था,वह पढ़ाये गये पाठ यथाशीघ्र सीख शिक्षा के सोपान चढ़ने लगा। सालगा में शुरुआती शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई कहां हो,इस प्रश्न का उत्तर पिता सुगना मुंडा को जर्मन मिशन स्कूल चाईबासा खींच ले गया। मिशनरी संस्थाएं सेवा और शिक्षा के बहाने वनवासी समाज का धर्मांतरण करने के अपने छिपे उद्देश्य को पूरा करने में जुटी थीं। अब शिक्षा का द्वार तभी खुलने वाला था जब परिवार ईसाई मत स्वीकार करे। अंततः 1886 को बिरसा को स्कूल में प्रवेश मिला और परिवार को ईसाई धर्म में। सन् 1890 तक बिरसा मिशन स्कूल में पढ़ते रहे। यहां बिरसा



समझ सके कि वनवासी समाज के शोषण का कारण उनकी अशिक्षा,अंधविश्वास और घोर गरीबी है। मिशनरी का छिपा उद्देश्य भी वह समझ गये। पुरखों की परम्परा एवं स्वधर्म पर अडिग विश्वास ने बिरसा को मूल धर्म की मुख्य धारा की ओर मोड़ दिया। मिशनरी स्कूल ने बिरसा के माध्यम से मतांतरण के स्वप्न को पूरा होते न देख,उसे स्कूल से निकाल दिया। 15 वर्ष का वह किशोर गांव वापस आ गया और सत्य की खोज में जुट गया। इसी बीच एक संत से तीन वर्ष तक वैष्णव सम्प्रदाय के बारे में जाना-समझा और तब मांसाहार त्याग हल्दी से रंगी सूती धोती और खड़ाऊं पहन समाज जागरण के काम में लगे। बचपन में मौसी के गांव में बांसुरी और इकतारा तुइला बजाने में प्राप्त कुशलता तथा वाणी कि मधुरता लोगों को आकर्षित करने का साधन बन गई थी।

जर्मन मिशन स्कूल छोड़ने के बाद बिरसा वनवासियों का संगठन करने,जमींदारी प्रथा एवं राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध लोक जागरण करने के पथ पर अग्रसर हुए। मुंडा,उरांव और खारिया जनजातियों के युवक-युवतियों और बड़े-बुजुर्गों से तार्किक संवाद कर अंधविश्वास की जकड़न से दूर कर शिक्षा के महत्व से परिचित कराया। बीमारियो के लिए उचित चिकित्सा की राह दिखाई। फलतःसभी जनजातियां एक सूत्र में गुंथ-एकत्रित हो सुवासित हार बन गईं। इस कारण ईसाई मिशनरियों का भात-भोजन,कपड़ा और दवाई का लालच देकर ईसाई पंथ में मतांतरित करने का कार्य बाधित हुआ,साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की लूट के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह से अंग्रेजी सत्ता का क्रोध भी चरम पर पहुंचने लगा था। इसी दौरान बिरसा मुंडा वनवासियों की सुरक्षा और अंग्रेजों से युद्ध के लिए एक सुरक्षित स्थान डंबारी पहाड़ी को अपना ठिकाना बनाया जो घने जंगलों एवं ऊबड़-खाबड़ रास्तों के कारण अंग्रेजी सेना की पहुंच से दूर था। बिरसा मुंडा ने बिरसाइत मत की स्थापना की और गांव-गांव घूमते,लोगों के बात कर समझाते। वनवासी उनकी बातों को ध्यान से सुनते, विश्वास करते और उनके प्रति श्रद्धा-सम्मान समर्पित करते। वनवासी समाज बिरसा मुंडा को एक अलौकिक व्यक्तित्व समझने लगा था। उनकी एक आवाज पर मुंडा, खारिया,उरांव जनजाति के हजारों युवक-युवतियों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका। विद्रोह का नाम दिया- उलगुलान अर्थात् महान विद्रोह। बिरसा ने नारा दिया-अबुआ राज एते जाना,महारानी राज कुंडू जाना (रानी का राज समाप्त है और अपना राज आरंभ हुआ)। यह नारा लोगों का कंठहार बना गया। जगह-जगह विद्रोह होने लगा। अंग्रेज सिपाही मारे जाने लगे। 1899 में क्रिसमस के अवसर पर रांची के चर्च,जमींदारों के मकानों और थानों को जलाने का प्रयास हुआ। 5 जनवरी,1900 को दो सिपाही मौत के घाट उतार दिए और खूंटी थाना पर जोरदार हमला किया। इन हमलों से अंग्रेज बौखला गये और बिरसा मुंडा की जानकारी देने वाले को 500 रुपये का इनाम घोषित किया। इनाम के लालच में एक व्यक्ति ने डंबारी पहाड़ी का गुप्त रास्ते का पता बता दिया। डंबारी पहाड़ी पर 9 जनवरी, 1900 को सुबह से मुंडा,उरांव,खारिया जनजाति के हजारों वनवासी स्त्री-पुरुषअपने परम्परागत हथियारों के साथ इकट्ठा हो रहे थे। उलगुलान का उत्साह हिलोरें मार रहा था। बिरसा एकत्रित समाज को सम्बोधित कर अगली योजना पर बातचीत कर रहे थे,कि तभी बिना किसी चेतावनी के गोलियों की तड़तड़ाहट से पहाड़ी गूंज गई। वृक्षों पर बैठे पक्षी उड़ने लगे। सियार-लोमडी इधर-उधर भागने लगे। अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को घेर लिया था, वनवासियों ने विरोध किया पर अचानक हुए हमले से सैकड़ों लाशों से पहाड़ी पट गई। जलियांवाला कांड के बीस साल पहले हुआ यह बड़ा नरसंहार था पर इतिहास में इसकी वैसी चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि अंग्रेजों ने इस घटना को दबा दिया। हमले के बीच से अनुयायी बिरसा मुंडा को सुरक्षित निकाल ले जाने में सफल हुए। सिपाही पीछे पड़े रहे। जासूसों का जाल फैला हुआ था। और 3 फरवरी,1900 को बिरसा मुंडा घने जंगल के मध्य सोते समय साथियों के गिरफ्तार कर रांची जेल में कैद कर दिए गये। 460 आरोपितों पर 15 विभिन्न मुकदमे चलाए गये। जिला जज ने जेल से न्यायालय तक बिरसा को पैदल लाने का आदेश दिया ताकि वनविसी समाज में संदेश जा सके कि अंग्रेजों के विरुद्ध सिर उठाने का परिणाम क्या होता है। न्यायलय में पेशी के दिन सड़क के दोनों ओर हजारों लोग बिरसा मुंडा की जय-जयकार करते हुए फूल बरसा रहे थे। जज को बिरसा के विरुद्ध उचित साक्ष्य नहीं मिले,मुकदमा कमजोर था किंतु बिरसा को छोड़ना मंजूर न था। अतः खानापूर्ति कर जेल भेज दिया गया। जेल अधिकारियों ने साजिशन बिरसा की दातुन और भोजन में धीमा विष मिलाना आरम्भ किया, परिणामतः 9 जून, 1900 को रांची जेल में मां भारती का वीर सपूत लौकिक जीवन पूर्ण कर हमेशा के लिए प्रत्येक भारतीय के हृदय में बस गया। बिरसा मुंडा की स्मृति को संजोने के लिए सरकारों ने सड़कों,संस्थानों के नाम उन पर रखे,चौराहों पर मूर्तियां स्थापित किया ताकि भारत की भावी पीढ़ी प्रेरित होती रहे।

धरती आबा बिरसा मुंडा, क्रांति के महानायक

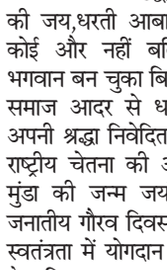




संजय एम. तराणेकर
इन्दौर, मध्यप्रदेश

जंगल की धरा में जन्मा,
वीर सपूत निराला था,
अन्यायों से टकराता,
वो साहस की ज्वाला था।
आदिवासी अस्मिता हेतु,
संघर्ष बिगुल बजाया,
शोषण-अत्याचारों विरुद्ध,
स्वाभिमान जगाया।
न धन लोभ-न सत्ता चाह,
अपनी माटी से प्यार,
जल,जंगल-जमीन के लिए,
संघर्ष ही हथियार।
अंग्रेजी हुकूमत थर्राती,
गूंजती बिरसा हुंकार,
उलगुलान नारा देकर,
बदला संघर्ष का संसार।
पच्चीस वर्ष की आयु में,
इतिहास अमर कर गए,
जनजातीय गौरव प्रतीक बन,
अभिमान बन गए।
आज गूंज रहीं उनकी गाथा,
वनवासी अरमानों में,
धरती आबा अमर रहेंगे,
भारत के वीर जवानों में।

जब इंसान सही रास्ते पर चलते हुए भी थक जाता है, तो फिर वो हमेशा के लिए ख़ामोश हो जाता है...



डॉ.मुश्ताक अहमद
हरदा,मध्यप्रदेश

थका हुआ मुसाफिर और जिंदगी का सच,

जिंदगी कोई सीधी और हमवार सड़क नहीं है। यह कांटों,उतराइयों और अंतहीन मोड़ों से भरा एक ऐसा सफ़र है,जहाँ हर क़दम पर परीक्षा होती है। इस सफ़र में एक ऐसा भी पड़ाव आता है, जब इंसान तमाम उम्र सच्चाई के रास्ते पर चलते-चलते,उसूलों का बोझ ढोते-ढोते अंदर से इस क़दर टूट जाता है कि वह अपनी ही आवाज़ खो बैठता है। जब इंसान सही रास्ते पर चलते हुए भी थक जाता है,तो फिर वह हमेशा के लिए ख़ामोश हो जाता है,वह अपनी उन तमाम क़ुर्बानियों को भुलाना चाहता है, जो उसने अपने बच्चों और अपनों के लिए दी थीं। यही हादसा उसे बेमौत मरने पर मजबूर कर देता है।

उसूलों का सफ़र और तन्हाई का बोझ

सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता सुनने में भले ही बड़ा और पवित्र लगे,लेकिन इस पर चलना उतना ही कांटों भरा होता है। इस रास्ते का मुसाफ़िर अक्सर अकेला रह जाता है। वह अपने हिस्से की खुशियों को ताक़ पर रखकर,अपनों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी रातों की नींद और दिनों का सुकून क़ुर्बान कर देता है। वह बच्चों की हर मुस्कान के पीछे अपने आंसुओं को छुपाता है। वह सोचता है कि उसकी मेहनत और त्याग उसके परिवार की दुनिया रोशन कर देंगे। लेकिन विडंबना यह है कि जब उम्र के ढलान पर उसे थोड़ी सी छांव,अपनापन और दो मीठे शब्दों



की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है,तब उसे या तो उपेक्षा मिलती है या फिर अपनों की ख़ामोशी

क़ुर्बानियों का बिसरना और भीतर का सूनापन, एक पिता,एक अभिभावक जब अपनी पूरी उम्र दूसरों को सींचते हुए बिता देता है,और बदले में उसे अकेलापन मिलता है,तब उसका मन विद्रोह नहीं करता,बल्कि वह थक जाता है। वह अपनी उन तमाम क़ुर्बानियों को अपनी ही स्मृति से मिटाना चाहता है,जो उसने अपने बच्चों के लिए दी थीं। क्यों? क्योंकि जब त्याग का सिला दर्द बन जाए,तो वे यादें ही नासूर बन जाती हैं। वह चाहकर भी उन पलों को याद नहीं करना चाहता, जिन्हें उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर जिया था। यह बिसरने की चाहत दरअसल उसके उस दर्द से भागने की छटपटाहट है,जो भीतर ही भीतर उसे खा रहा होता है।

बेमौत मरने का मौन हादसा,

सांसों का थम जाना ही मौत नहीं है। जब किसी इंसान की उम्मीदें, उसकी आस्था और उसका आत्म सम्मान एक-एक करके दम तोड़ने लगते हैं, तो वह शारीरिक रूप से जीवित रहते हुए भी भीतर से मर चुका होता है। यही वह आंतरिक हादसा है जो उसे बेमौत मरने पर मज़बूर कर देता है। बाहरी दुनिया के लिए वह जीवित होता है, लेकिन उसकी आँखें बुझ चुकी होती हैं, उसका उत्साह ख़त्म हो चुका होता है और वह जिंदगी की भीड़ में सबसे अकेला महसूस करता है।

यह आलेख सिर्फ़ एक शख्स की दास्तान नहीं है,बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच का आईना है जहाँ रिश्तों की गर्माहट कम होती जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनों के त्याग को समझें। इससे पहले कि कोई मुसाफ़िर सही रास्ते की थकान और अपनों की बेरुखी से तंग आकर हमेशा के लिए ख़ामोश हो जाए,हमें उसकी ख़ामोशी को पढ़ना होगा। उसक सम्मान का हाथ थामना होगा, ताकि किसी को भी अपनों के बीच रहकर यूं बेमौत न मरना पड़े।

गंदे पानी की बोतल



डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा
उतृत

बाबू गुस्से में फाइलें पटकते हुए डांटकर कहता कि अरे पंडित जी जब तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डिजिटल डैशबोर्ड पर बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का रियल टाइम डेटा अपलोड नहीं होगा तब तक फूटी कौड़ी नहीं छूटेगी और तुम इस बदबूदार बोतल को लेकर ताउम्र यहीं चक्कर काटते रहोगे। गंगाधर बाबू बिना किसी प्रतिवाद के वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते और उस मटमैली बोतल को धूप की रोशनी में उठाकर उसके तल में जमी कालिख को निहारने का निरर्थक प्रयास करने लगते थे जो हर बार एक बेबस सिसकी बनकर हवा में खो जाती थी। कस्बे के लोग आपस में तरह-तरह की बातें करते थे कि शायद पंडित जी अपने किसी घाट के मुआवजे के लिए यह सब कर रहे हैं लेकिन किसी को भी उस बोतल और गंगा दिवस के इस भव्य आयोजन के बीच छुपे भयानक रहस्य की ज़रा सी भी भनक नहीं थी।

दोपहर में अचानक केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक महोदय राष्ट्रीय गंगा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करने और नए डिजिटल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम का लोकार्पण करने मुख्यालय पहुँचे। साहब की गाड़ी का सायरन बजते ही पूरे परिसर में खलबली मच गई और आनन-फानन में स्वागत के लिए नए डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड और लाल कालीन बिछाया जाने लगा ताकि कोई कमी न दिखाई दे। मंच पर दीप प्रज्वलन और पतित पावनी गंगा को स्वच्छ एवं अविरल बनाने के सरकारी संकल्प पर लंबा भाषण देने के बाद जब महानिदेशक महोदय पत्रकारों की भीड़ के साथ बाहर निकले तो उनकी नज़र चबूतरे पर शांत बैठे गंगाधर बाबू पर पड़ी जिनकी गोद में वही मटमैली बोतल रखी थी। अपनी संवेदनशील और जनप्रिय छवि का प्रदर्शन करने के लिए साहब तुरंत मीडिया कर्मियों को साथ लेकर गंगाधर बाबू के पास पहुँचे और बड़े आदर से बोले कि तीर्थ पुरोहित जी आज राष्ट्रीय गंगा दिवस पर हम मां गंगा के प्रहरियों को नमन करते हैं बताइए आपकी क्या पीड़ा है क्या आपको विभाग की किसी घाट संरक्षण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है जिसे मैं तुरंत स्वीकृत करवाऊँ। गंगाधर बाबू ने अपनी पथराई आँखों से महानिदेशक को देखा और अपने कांपते हाथों से वह गंदले पानी की बोतल आगे बढ़ाते हुए बोले कि साहब जी अगर वाकई न्याय करना चाहते हैं तो ज़रा इस बोतल पर चिपकी इस सरकारी लैब रिपोर्ट का सच पहचान लीजिए।

महानिदेशक ने जब उस बोतल को हाथ में लेकर गौर से देखा तो उस पर पंद्रह साल पुरानी तारीख के साथ उसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तकनीकी स्वीकृति दर्ज थी जिस पर खुद उनके अपने हस्ताक्षर थे। गंगाधर बाबू की आँखों से आंसुओं के दो मोटे कतरे ढलककर उस प्लास्टिक पर गिर पड़े और वे रुंधे गले से बोले कि साहब पंद्रह साल पहले जब आपके विभाग ने हमारे पुश्तैनी घाट के ठीक सामने बीस करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का दावा किया था तो मैंने अपनी पुरखों की जमीन बिना एक पैसा लिए सरकार को दान दे दी थी कि मां गंगा का आंचल मैला नहीं होगा। लेकिन आपके ठेकेदारों और अफसरों ने प्लांट को कागजों पर चालू दिखाकर पूरा बजट हड़प लिया और शहर भर के नालों का जहरीला केमिकल सीधे गंगा मैया की छाती पर उड़ेल दिया। उसी जहरीले पानी में स्नान करने के कारण मेरे इकलौते होनहार नाविक बेटे के दोनों फेफड़े गल गए और वह आज बिस्तर पर जिंदा लाश बनकर सांसों की भीख मांग रहा है जबकि आपके दफ्तर ने मुझे यह कहकर भगा दिया कि नदी अब पवित्र हो चुकी है। मैं रोज़ यह गंदा पानी यहाँ इसलिए लाता हूँ ताकि आपके इस चमकते मंच को बता सकूँ कि जिस गंगा दिवस पर तुम शुद्धिकरण का ढोंग रचते हो तुम्हारी उसी भ्रष्ट व्यवस्था ने पवित्र जल के नाम पर एक गरीब परिवार की खुशियों को जीते-जी नाबदान में बहा दिया है। यह सुनते ही महानिदेशक का सिर शर्म से झुक गया और पूरा मुख्यालय परिसर गहरे सन्नाटे में डूब गया।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

C M Y K

सरहरी में धूमधाम से मनाया गया... जनजातीय गौरव दिवस एवं बाल दिवस

सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया

न्योता भोज व पुरस्कार वितरण के साथ हुआ दो दिवसीय आयोजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरहरी में जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं बाल दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन तथा छत्तीसगढ़ राज्य गीत के गायन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज वर्चुअल माध्यम से जुड़े, साथ ही सरपंच मीनमती मंच पर मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत प्रतापपुर की जनपद सदस्य कुंती शिवपाल कुशवाहा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय नारायण कुशवाहा,प्रेमचंद कुशवाहा, रूद्र प्रसाद कुशवाहा,उपसरपंच श्रीमती उषा देवी, शिवचरण नापित,अरविंद पटेल एवं रामनाथ यादव उपस्थित रहे।



महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का आह्वान : अपने वर्चुअल उद्बोधन में अपने सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने क्षेत्रवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान के साथ-साथ सरगुजा संभाग के जनजातीय गौरव माता राजमोहिनी देवी और संत गहिरा गुरु के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से उनके बताए मार्ग पर सतत् चलने का आह्वान किया। स्वागत उद्बोधन में संस्था के प्राचार्य दिलीप तिवारी ने संत-महापुरुषों की जीवनी को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। इसके पश्चात कक्षा 11वीं की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। सभा को विजय नारायण कुशवाहा,अरविंद पटेल,शिवचरण नापित,सरपंच मीनमती एवं जनपद सदस्य कुंती शिवपाल कुशवाहा ने भी संबोधित किया।

दूसरे दिन मनाया गया बाल दिवस, बच्चों ने चखा न्योता भोज का स्वाद : जनजातीय गौरव सप्ताह के दूसरे दिन विद्यालय में'बाल दिवस' का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य दिलीप तिवारी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू (चाचा नेहरू) के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार के स्टाफ द्वारा सभी बच्चों के लिए विशेष रूप से न्योता भोज का आयोजन किया गया, जिसे बच्चों ने बड़े ही रुचिपूर्वक ग्रहण किया और अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

विविध प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

राज्यपाल पुरस्कृत व्याख्याता अजय कुमार चतुर्वेदी के संयोजन एवं संचालन में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 8 वर्गों में विभाजित कर 5 राउंड की रोमांचक 'जनजातीय गौरव क्विज प्रतियोगिता' कराई गई। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण जनजातीय गौरव रंगोली, चित्रकला, भाषण और सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिताएं रही।

व्रतियों ने किया खरना,36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू,पहला अर्घ्य आज



-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

लोकआस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन शनिवार को छठव्रतियों ने तालाबों,जलाशयों नदियों में स्नान करने के बाद प्रसाद बनाया। शाम में शांत वातावरण में खरना का धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर प्रसाद ग्रहण किया। व्रतियों के प्रसाद खाने के बाद परिवार के अलावा पड़ोसी,रिश्तेदारों का प्रसाद खाने का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। इसके साथ ही तकरीबन 36 घंटे का व्रतियों का निर्जला उपवास शुरू हो गया। रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके लिए व्रती तालाब, नदी, डेम में स्नान कर शाम में भगवान भुवन भास्कर को पहला अर्घ्य देंगे। फिर सोमवार की सुबह जलाशयों में उतरकर भगवान की आराधना करेंगे। साथ ही उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे, इसके साथ ही चार दिवसीय महा छठ की पूर्णाहुति होगी।

शुद्धता का रखा पूरा ध्यान : खीर प्रसाद बनाने के लिए नदियों और कुएं के पानी इस्तेमाल किया। नए चूल्हे पर आम की लकड़ी को जलावन में इस्तेमाल करते हुए पीतल के बर्तन में खरना के लिए प्रसाद बनाया गया। प्रसाद के लिए खीर व पूरी बनाई। शाम ढलते ही छठ व्रतियों ने छठ गीतों के बीच प्रसाद ग्रहण किया।

छठ घाट व्रतियों के लिए तैयार : लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए शंकर घाट, घुनघुट्टा नदी का छठ घाट, शिवधारी कॉलोनी, शिवसागर बांध सहित अन्य छठ घाट व्रतियों के लिए पूरी तरह तैयार है। शंकर घाट पर महामाया छठ सेवा समिति द्वारा तैयारी की गई है। घुनघुट्टा में श्याम सेवा समिति, ग्राम पंचायत उदयपुर ढ़ाब स्थित उत्तर वाहिनी घुनघुट्टा नदी तट पर श्रीराम घाट छठ पूजा सेवा समिति द्वारा तैयारी की गई है।

व्रतियों ने घाट बांधकर की पूजा : चार दिवसीय छठ के दूसरे दिन रविवार को व्रतियों ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को छठ घाट पर जाकर नदी-तालाबों व जलाशयों में स्नान करने के बाद नदी के ही रेत व मिट्टी को उठाकर घाट बांधने के बाद पूजा अर्चना की।

खरीददारी का सिलसिला जारी : इधर रविवार को बाजार में काफी रौनक रही। लोग पूजन सामग्री,फल अन्य सामान की खरीददारी करने में व्यस्त रहे। शहर के गुदरी बाजार में जगह-जगह गन्ना, सूप-दउरा,पूजन सामग्री आदि के स्टॉल लगाए गए हैं।

विश्व मधुमेह दिवस पर मेडिकल कॉलेज में सीएमई आयोजित

विशेषज्ञों ने दिए मधुमेह के शुरुआती निदान और उपचार के टिप्स, टाइप-1 मरीजों ने साझा किए अनुभव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (आरएसडीकेएस जीएमसी),अंबिकापुर के मेडिसिन विभाग एवं एनजीओ 'सावरी' के संयुक्त तत्वावधान में विशेष सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम 'मधुमेह पर शुरुआती कार्रवाई' (अर्ली एक्शन ऑन डायबिटीज) रही। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने समय पर जांच, उपचार और बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में करीब 200 लोग शामिल हुए। इनमें डॉक्टर,एमबीबीएस एवं पीजी के विद्यार्थी, नर्सिंग छात्र और मरीज शामिल थे। मेडिसिन विभाग के डॉ. एमडी शानिल ने अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इसके बाद संस्थान के डीन डॉ.अविनाश मेघ्राम ने मधुमेह के बढ़ते प्रभाव और शुरुआती निदान के महत्व पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों ने इंसुलिन के उपयोग एवं मधुमेह प्रबंधन, मधुमेह से होने वाली किडनी संबंधी बीमारियों तथा संतुलित आहार की भूमिका पर व्याख्यान दिए। इसके साथ ही टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित मरीजों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि बीमारी के बावजूद सकारात्मक सोच और नियमित देखभाल के साथ जीवन जिया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।



कुत्ते के बच्चों को बेरहमी से मारकर जलाया एफआईआर दर्ज करने सौंपा आवेदन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के पंजाब गार्डन के पीछे 6 कुत्ते के बच्चों को बेरहमी से मारकर जलाने और बोरी में भरकर फेंकने का मामला सामने आया है। घटना 13 नवंबर को शाम करीब 4.30 बजे की बताई जा रही है। मामले को लेकर बेजुबान डॉग शेल्टर के संस्थापक सुधांशु शर्मा ने गांधीनगर थाने में लिखित शिकायत देकर दोषियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, अज्ञात लोगों ने 6 बेजुबान पिल्लों को बेरहमी से मारने के बाद बोरी में भरकर जला दिया। घटना से इलाके के पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश है। शेल्टर संस्थापक सुधांशु शर्मा ने पुलिस के संज्ञान में इस मामले को लाया है और घटना के जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं और दोषियों की पहचान करके उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बेजुबान जानवर भी दर्द महसूस करते हैं। उनके साथ ऐसी बर्बरता न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। इस पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।



साइबर ठगी के लिए म्यूल अकाउंट देने वाला गिरफ्तार दो राज्यों में 1 लाख से अधिक की ठगी का मामला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

साइबर ठगी करने वाले गिरोहों को अपना बैंक खाता किराए पर देने वाले म्यूल अकाउंट धारकों पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सरगुजा साइबर सेल की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2024 के प्रकरण में अंबिकापुर के एक युवक के विरूद्ध अपराध दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के समन्वय पोर्टल पर दो राज्यों से एक लाख से अधिक की ठगी संबंधी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसकी सूची पुलिस महानिरीक्षक एसआईबी,सीसीटीएनएस साइबर क्राइम,नवा रायपुर डॉ. ध्रुव गुप्ता के कार्यालय से पुलिस अधीक्षक सरगुजा को भेजी गई थी। इसमें गुजरात राज्य के जिला कानबा, थाना अहमदाबाद रूरल से 1,03,495 रुपये और राजस्थान राज्य के जिला जयपुर,थाना कानोता से 3,980 रुपये की ठगी का मामला संज्ञान में लाया गया था। साइबर सेल सरगुजा के नोडल अधिकारी से प्राप्त पत्र का अवलोकन करने पर कोतवाली थाना पुलिस ने पाया कि मोबाइल नंबर धारक रितिक रौशन एक्का पिता बेंजामिन एक्का,निवासी गोधनपुर वसुन्धरा विहार के पीछे का एचडीएफसी बैंक में खाता है,जिसका म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग हुआ है।

गांधी स्टेडियम और चौपाटी से बाइक उड़ाता रहा शातिर चोर,पुलिस ने 5 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ दबोचा

3 लाख का मशरू का बरामद,एक चोरी की रिपोर्ट से खुलीं चार अन्य वारदातें;बिहार का रहने वाला आरोपी केदारपुर में बना था ठिकाना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर में सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी दोपहिया गाड़ियां कितनी सुरक्षित हैं,यह गांधी स्टेडियम और चौपाटी से हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं से समझा जा सकता है। शातिर चोर एक के बाद एक पांच मोटरसाइकिलों को निशाना बनाता रहा और वाहन मालिकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि, एक मोटरसाइकिल की चोरी की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो चोरी की चार अन्य वारदातों का भी खुलासा हो गया। पुलिस ने बिहार निवासी 50 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे और निशानदेही पर पांच मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद वाहनों की कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई गई है।



एक शिकायत ने खोली चोरी की पांच वारदातों की परतें : मामले की शुरुआत 12 नवंबर 2026 को हुई, जब गांधीनगर थाना क्षेत्र के महुआपारा निवासी आदित्य कुजूर अपनी होंडा ड्रीम युगा मोटरसाइकिल क्रमांक CG-15-DK-2980 से गांधी स्टेडियम पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बाइक स्टेडियम के बाहर खड़ी की थी। कुछ देर बाद लौटे तो मोटरसाइकिल गायब थी। काफी तलाश के बाद भी वाहन नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 790/26, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मुखबिर की सूचना पर पकड़ाया आरोपी : लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने कोतवाली पुलिस को त्वरित कार्रवाई और चोरी के वाहनों की बरामदगी के निर्देश दिए। जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध विजय गुप्ता को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम विजय गुप्ता (50), पिता इन्द्रदेव गुप्ता,निवासी डेहरी कोयला डिपो के पास, थाना डेहरी, जिला रोहतास (बिहार), वर्तमान निवास केदारपुर,अंबिकापुर बताया।

पुलिस के मुताबिक,पूछताछ में आरोपी ने गांधी स्टेडियम के बाहर से आदित्य कुजूर की होंडा ड्रीम युगा चोरी करना स्वीकार किया। इसके अलावा एक बजाज सीटी, एक स्प्लेंडर प्लस और दो होंडा ड्रीम शाइन मोटरसाइकिल चोरी करने की बात भी कबूल की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने पांचों मोटरसाइकिलें बरामद कीं।

सवाल भी कम नहीं : सार्वजनिक स्थलों पर वाहन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

पांच मोटरसाइकिलों की बरामदगी पुलिस के लिए उपलब्धि जरूर है,लेकिन शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती हैं। गांधी स्टेडियम और चौपाटी जैसे व्यस्त स्थानों पर वाहन चोरी होना बताता है कि वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है। ऐसे स्थानों पर निगरानी और पुलिस गश्त कितनी प्रभावी है, इसकी समीक्षा भी जरूरी है। एक मामले के खुलासे के बाद चार अन्य चोरी की वारदातों का सामने आना यह भी बताता है कि ऐसी घटनाओं पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की है। पूरी कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश सिंह,सहायक उप निरीक्षक आलोक सोनी, प्रधान आरक्षक सूरज राय,सियाराम मरावी,सदरक लकड़ा तथा आरक्षक विवेक राय, नितिन सिन्हा और शिव राजवाड़े की सक्रिय भूमिका रही।

मुक्तिबोध के साहित्य में दिखा समकालीन यथार्थ का आईना,वैचारिक प्रतिबद्धता पर हुआ मंथन

होलीक्रॉस वीमेंस कॉलेज में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित,युवा कवयित्रियों ने रचनाओं से बांधा समां

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

साहित्य केवल समाज का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसकी विसंगतियों से टकराकर बदलाव की राह तलाशने का माध्यम भी है। हिंदी साहित्य के प्रखर कवि,कथाकार और चिंतक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं इसी वैचारिक संघर्ष और सामाजिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। उनके जन्मदिवस के अवसर पर होलीक्रॉस वीमेंस कॉलेज, अंबिकापुर के हिंदी विभाग एवं अध्ययन एवं शोध केंद्र द्वारा 13 नवंबर को 'मुक्तिबोध स्मरण' के तहत एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। 'मुक्तिबोध का रचनात्मक संसार और समकालीन यथार्थ'विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्य की सामाजिक भूमिका,मुक्तिबोध की वैचारिक प्रतिबद्धता और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता पर गंभीर विमर्श हुआ। कार्यक्रम के प्रथम सत्र की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. (सि.) शांता जोसेफ ने की। मुख्य वक्ता महेश वर्मा ने मुक्तिबोध के साहित्य का विश्लेषण करते हुए कहा कि समकालीन यथार्थ की जटिल चुनौतियों के बीच साहित्य बदलाव की संभावनाओं के लिए नई राहें खोलता है। उन्होंने मुक्तिबोध की रचनाओं में मौजूद वैचारिक गहराई, जीवन-दृष्टि और सामाजिक अंतर्विरोधों को रेखांकित करते हुए बताया कि बदलते समय में भी उनकी रचनाएं किस तरह प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने छात्राओं को साहित्य को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखते हुए उसे व्यापक सामाजिक और वैचारिक संदर्भों में समझने की प्रेरणा दी।



अतिथि वक्ता डॉ. कामिनी ने मुक्तिबोध के गद्य साहित्य, विशेषकर उनकी कहानियों पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध की कहानियां उपभोक्तावादी संस्कृति, मध्य वर्गीय मानसिकता,सामाजिक विडंबनाओं और व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्वों को बेहद सूक्ष्मता से उजागर करती हैं। उनका कथा साहित्य व्यक्ति और समाज के बीच मौजूद अंतर्विरोधों को समझने की दृष्टि प्रदान करता है।

युवा कवयित्रियों ने कविताओं से रखे अपने विचार : सेमिनार के द्वितीय सत्र में युवा कवयित्रियों का काव्यपाठ आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रो. विश्वासी एक्का ने की। उन्होंने मुक्तिबोध की कविताओं का संदर्भ देते हुए कहा कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, सत्य के पक्ष में निर्भीकता से खड़े रहना जरूरी है। उन्होंने युवा रचनाकारों को लेखन के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि मन में विचार आते ही उन्हें शब्दों में ढालना चाहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास और लेखन से ही रचनात्मकता विकसित होती है। इस सत्र में रितिका, रजनी, अंजुला, स्नेहा और प्रज्ञा ने अपनी स्वरचित कविताओं का पाठ किया। युवा कवयित्रियों की रचनाओं में उनकी संवेदनाएं और रचनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिली। वहीं, अर्चना यादव द्वारा बनाया गया मुक्तिबोध का स्केच भी कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। सेमिनार के माध्यम से मुक्तिबोध के साहित्य, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, सामाजिक सरोकारों और समकालीन समय में उनकी प्रासंगिकता पर सार्थक संवाद हुआ। कार्यक्रम ने छात्राओं को साहित्य के प्रति संवेदनशीलता के साथ आलोचनात्मक और वैचारिक दृष्टि विकसित करने का अवसर दिया।

कार्यक्रम का संयोजन हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. मृदुला सिंह ने किया। आयोजन समिति में सुश्री कविता एक्का एवं सुश्री सुमन भगत की सक्रिय सहभागिता रही। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।

डेली नीड्स के संचालक पर सेल्समैन ने लगाया मारपीट का आरोप

-संवाददाता-
उदयपुर ,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। बकाया पैसे के लेन-देन को लेकर रास्ता रोककर डेली नीड्स के संचालक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस केस दर्ज करके मामले में अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर जिला के प्रेमनगर थाना अंतर्गत केदारपुर निवासी अनुराग सोनी पिता रितेश कुमार सोनी 20 वर्ष, पिछले 2 साल से मित्तल सेल्स कंपनी अंबिकापुर में सेल्समैन का काम करता है। 13 नवम्बर को दोपहर 01.30 बजे वह ओम डेली नीड्स उदयपुर में बकाया पैसा मांगने गया तो संचालक प्रिंस ने कुछ देर बाद आने के लिए कहा। एक घंटे बाद दोपहर 02.30 बजे दोबारा रुपये लेने गया तो प्रिंस ने रुपये नहीं होने की बात कही। जब अनुराग ने कंपनी के मालिक से बात करने के लिए कहा तो डेली नीड्स का संचालक भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए उसे उदयपुर से बाहर निकल कर दिखाओ, कहते हुए धमकाने लगा। आरोप है कि जब वह वापस अंबिकापुर जा रहा था, तब उदयपुर में ही बालाजी मेडिकल के सामने प्रिंस ने अपने भांजे और अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे जबरन रोका और गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्का और लाठी-डंडे से मारपीट करने लगा, जिसमें उसे अंदरूनी चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में आरोपितों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।

CMYK

मतदाता सूची की कथित गड़बड़ियों पर कांग्रेस की जन चौपाल..चिरमिरी और नागपुर चौराहे में उठी 'वोट बचाओ-देश बचाओ' की आवाज

डॉ.चरणदास महंत,सांसद ज्योत्सना महंत और अभियान प्रभारी डॉ. देवाशीष पटनायक ने मताधिकार की सुरक्षा को बताया लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत







-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़/एमसीबी,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और मताधिकार की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने चिरमिरी के पोड़ी क्षेत्र और नागपुर चौराहे में जन चौपाल आयोजित की,छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के तहत आयोजित इन कार्यक्रमों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लोकतंत्र,निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों को लेकर अपनी बात रखी, नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पात्र नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है, उन्होंने आम नागरिकों से अपने और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांचने की अपील की,जन चौपाल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक एवं अभियान प्रभारी डॉ. देवाशीष पटनायक,छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत तथा सांसद ज्योत्सना महंत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे,दोनों स्थानों पर आयोजित संवाद कार्यक्रमों में मतदाता सूची की पारदर्शिता,विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और कथित वोट चोरी के आरोपों पर चर्चा की गई।

हर मतदाता अपने नाम की जांच करे- नेताओं ने नागरिकों से अपील की कि वे केवल मतदान के दिन सक्रिय होने के बजाय मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान भी सजग रहें, प्रत्येक परिवार अपने सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांचे,नाम में गलती,पता संबंधी त्रुटि अथवा किसी पात्र सदस्य का नाम सूची में नहीं होने जैसी स्थिति सामने आने पर नियमानुसार सुधार और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनाएं,उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया, नेताओं के अनुसार अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं को सामने लाना,नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को जनस्तर तक पहुंचाना है।

मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

जन चौपाल में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती केवल मतदान कराने से सुनिश्चित नहीं होती,बल्कि यह भी जरूरी है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे और उसे बिना किसी बाधा के मतदान का अवसर मिले,नेताओं ने मतदाता सूची में नामों की कथित गड़बड़ी,पात्र मतदाताओं के नाम छूटने,अन्य स्थानों से संबंधित नाम दर्ज होने और विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए,कांग्रेस नेताओं का कहना था कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना निर्वाचन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है,यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूट जाता है अथवा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम गलत तरीके से दर्ज होता है,तो इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल पैदा हो सकते हैं,हालांकि जन चौपाल में उठाए गए ये मुद्दे कांग्रेस की ओर से व्यक्त की गई आशंकाएं और आरोप हैं,जिनकी पुष्टि संबंधित निर्वाचन अभिलेखों और आधिकारिक जांच से ही हो सकती है।

लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं : कांग्रेस नेता- जन चौपाल में वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक ताकत नागरिक का मताधिकार है,प्रत्येक पात्र मतदाता को अपने मत का स्वतंत्र और निष्पक्ष उपयोग करने का अवसर मिलना चाहिए,मतदाता सूची में पारदर्शिता,निर्वाचन प्रक्रिया पर भरोसा और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी शर्तें हैं,कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के माध्यम से आम नागरिकों को मतदाता सूची से जुड़े विषयों की जानकारी दी जाएगी, कार्यकर्ता लोगों को सूची में अपना नाम देखने, त्रुटि मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार कराने और अपनी आपत्तियां संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे।

वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की रही मौजूदगी- कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरो,पूर्व विधायक डॉ. विनय जायसवाल, वासुदेव जी,ओम प्रकाश गुप्ता,रफीक मेमन, प्रभा पटेल,कृष्ण मुरारी तिवारी,बलबीर सिंह तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेश साहू सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे, इसके अलावा ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामनरेश पटेल सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अभियान में सहभागिता निभाई। जन चौपाल में रामा यादव,विष्णु दास,निर्मला चतुर्वेदी,शरण सिंह, सुरेन्द्र सिंह मखीजा,राजा राम कोल,कृष्णा, अमोल सिंह,अज्जू रवि,संदीप द्विवेदी,मकबूल अख्तर,श्याम दीवान,नीलिमा सामल,अमित दास, शिवांश जैन,आनंद राय,पिंटू भास्कर, जगदीश मधुकर,राजा पांडे और शाहनवाज अली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आम नागरिक मौजूद रहे।

बूथ स्तर तक अभियान पहुंचाने का संकल्प- जन चौपाल के समापन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मतदाता जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया,नेताओं ने कहा कि अभियान को केवल बैठकों और चौपालों तक सीमित नहीं रखा जाएगा,बल्कि गांवों, मोहल्लों और बूथ स्तर तक पहुंचकर नागरिकों से संवाद किया जाएगा,कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता,निष्पक्ष चुनाव और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा के मुद्दे पर जनजागरूकता जारी रहेगी,पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और मतदाता सूची से संबंधित समस्याओं के निराकरण में नागरिकों का सहयोग करने की अपील की,चिरमिरी और नागपुर चौराहे की जन चौपालों के जरिए कांग्रेस ने मतदाता सूची की कथित अनियमितताओं का मुद्दा स्थानीय स्तर पर उठाया,अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनजागरूकता के साथ-साथ मतदाताओं की वास्तविक शिकायतें संबंधित निर्वाचन अधिकारियों तक किस तरह पहुंचती हैं और उनका निराकरण किस प्रकार होता है।

लमगांव हनुमान मंदिर में घुसे चोरों ने 5 मूर्तियों से चांदी का मुकुट पार किया



-संवाददाता-
लुण्ड्रा,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना अंतर्गत लमगांव हनुमान मंदिर में मूर्तियों से चांदी का मुकुट चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। घटना को मंदिर में घुसकर तीन लोगों ने अंजाम दिया है,जो सीसीटीव्ही में कैद हो गए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष जगेश्वर गुप्ता पिता स्व. भण्डारी राम 65 वर्ष, निवासी ग्राम चोरकीडीह ने चैकी रघुनाथपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 12 नवम्बर को देर रात करीब 01.34 बजे अज्ञात चोर मंदिर परिसर में घुस गए और भगवान श्री राम,माता सीता लक्ष्मण जी और भगवान श्रीकृष्ण एवं राधा की मूर्तियों में लगे चांदी का परत चढ़े 5 नग मुकुट को चोरी करके ले गए। मुकुटों की कीमत लगभग 7 हजार रुपये है। मंदिर में लगे सीसीटीव्ही कैमरे में 3 व्यक्ति अंदर घुसते और बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं,लेकिन अंधेरा होने के कारण चेहरा स्पष्ट नहीं है। पुलिस चैकी में की गई शिकायत के आधार पर लुण्ड्रा थाना पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 331(4), 305(घ), 3(5) के तहत अपराध कायम करके विवेचना में लिया है, और सीसीटीव्ही में कैद हुए चोरों के तलाश में लगी है।

कुमकी हाथियों से रेस्क्यू जारी,उदयपुर में 18 स्कूल बंद,चिंघाड़ से थर्राया गांव

ग्रामीण बोले-26 हाथियों से ढाई महीने से परेशान,हाथियों का दल कुसुआमुड़ा में डटा...

-संवाददाता-
उदयपुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा में आतंक का पर्याय बन चुके लोनर हाथी कबरा कान 17 हाथियों के दल के मुखिया से संघर्ष के बाद कुसुआमुड़ा जंगल में डटा है। वन विभाग और ग्रामीणों के मुताबिक,रात करीब 10 बजे तक दोनों नर हाथियों के बीच भीषण लड़ाई चली। लड़ाई के दौरान जंगल में गूंजी तेज चिंघाड़ से पूरा सायर गांव थर्रा गया। लड़ाई में जीत के बाद कबरा ने पुराने मुखिया को ग्रुप से बाहर खदेड़ा और पूरे दल पर कब्जा कर लिया। वन विभाग को उम्मीद है कि हाथियों के समूह का मुखिया बनने के बाद कबरा कान हाथी के आक्रामक स्वभाव में बदलाव आ सकता है। लड़ाई के बाद कबरा हाथी दल के साथ लड़ाई स्थल से करीब दो किलोमीटर दूर कुसुआमुड़ा के जंगल में डटा है,जहां कुछ दिन पहले मादा हथिनी मृत पाई गई थी। यहां कबरा कान हाथी के साथ 18 हाथियों का दल एक साथ मौजूद है। ड्रोन के थर्मल इमेज में भी दल की लोकेशन वही मिली है। वन



विभाग का अमला और हाथी मित्र दल के एलीफेंट ट्रैकर लगातार निगरानी रख रहे हैं। वनरक्षक मुकेश कुमार राठौर का कहना है कि कबरा कान हाथी 17-18 महीने बाद उदयपुर परिक्षेत्र में प्रवेश किया है,जो बहुत ही आक्रामक और उत्पाती है। 12 नवम्बर को झिरमिट्टी में एक को मौत के घाट उतारने के बाद दो कुमकी हाथियों के माध्यम से ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ने का अभियान चलाया गया है,लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अभियान जारी रहेगा। इसे रेस्क्यू करने के बाद रमकोला रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाएगा।

घेराबंदी करके ट्रैंक्विलाइज की तैयारी : मौके पर मौजूद वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, लोनर एलिफेंट अपने झुंड से अलग रहता है। इस क्षेत्र में इसके द्वारा कई घटनाएं की गई हैं। अंबिकापुर, सूरजपुर,बलरामपुर इलाके तक इसकी दहशत है। शुक्रवार से ही उदयपुर में इसकी घेराबंदी करके ट्रैंक्विलाइज करने की तैयारी चल रही है। कुमकी हाथियों की टीम मौके पर है,डॉक्टर मौजूद हैं, फील्ड ट्रैकिंग का सिलसिला अनवरत जारी है। ट्रैंक्विलाइज टीम लास्ट लोकेशन के पास है। सुरक्षित स्थिति होने पर ही ट्रैंक्विलाइज की प्रोसेस पूरी की जाएगी।

ढाई महीने से 26 हाथियों का दल मंडरा रहा : ग्रामीण बृज कुमार सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि ढाई महीने से 26 हाथियों का दल उनके लिए खतरा बना हुआ है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। दो दिन पहले इस क्षेत्र में प्रवेश किया कबरा कान हाथी का खौफ कुछ अधिक ही है। काफी आक्रामक स्वभाव होने के कारण इलाके के लोगों की नींद उड़ गई है। छोटे-छोटे बच्चों के साथ ठंड में आग तापकर वे रतजगा करने विवश हैं।?घर के अंदर-बाहर वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जन-जीवन के लिए खतरा बने हाथी को सिर्फ रेडियो कॉलर लगाना पर्याप्त नहीं है, अभ्यारण्य में भेज देना चाहिए, ताकि हाथी भी सुरक्षित रहें और यहां की जनता और फसल भी सुरक्षित रहे।

सुरक्षा के चलते उदयपुर में 18 स्कूल बंद : कबरा हाथी की अनियमित चाल और आक्रामकता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एहतियात बरता है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हाथी झिरमिटी के जंगलों में था, तो झिरमिटी संकुल के 6 स्कूल बंद किए गए थे। शनिवार को सायर क्षेत्र में होने से सायर संकुल के 10 स्कूल और महेशपुर संकुल के 2 स्कूल, करीब डेढ़ दर्जन विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। रविवार को अवकाश रहने के कारण वैसे भी स्कूल बंद रहेंगे। प्रधान पाठकों को एसएमसी सदस्यों के माध्यम से बच्चों तक सूचना पहुंचाने के लिए कहा गया है।

अदानी माइंस के गेट पर हंगामा,कर्मचारियों को रोका,कंपनी को 22 लाख की क्षति

-संवाददाता-
उदयपुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

थाना क्षेत्र के परसा में स्थित अदानी माइंस में काम बाधित करने का मामला सामने आया है। कंपनी के एचआर हेड ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दी है,जिसमें कंपनी को 22 लाख का नुकसान पहुंचाने का उल्लेख है। जानकारी के मुताबिक, कर्मजीत सिंह कंपनी में एचआर हेड उत्पल विश्वास पिता गोपाल



विश्वास 25 वर्ष, निवासी ताहिरपुर नतुनपाड़ा, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल ने पुलिस को बताया है कि बीते 07 नवम्बर को द्वितीय पाली में दोपहर 02 बजे से रात 10 बजे तक काम करने वाले कर्मचारी,कंपनी के कॉलोनी से वाहन में सवार होकर माइंस के अंदर ड्यूटी में जाने के लिए निकले थे। इस दौरान कंपनी के मुख्य द्वार के सामने ग्राम परसा निवासी मोहे लाल उईके पिता नान्ही राम उईके अपनी मोटरसाइकिल बीच में खड़ी कर दी और कर्मचारियों को अंदर जाने से रोकने लगा। समझाने पर वह धमकी भरे लहजे में अभद्र व्यवहार करने लगा और जान से मारने की धमकी दी।

सूने मकान का ताला तोड़कर जेवरात समेत एक लाख का सामान चोरी

-संवाददाता-
दरिमा,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिला के दरिमा थाना अंतर्गत ग्राम सखौली में सूने मकान का ताला तोड़कर चोर ने पूरे घर को खंगाल डाला और जेवरात सहित एक लाख का सामान चोरी करके ले गए। जानकारी के मुताबिक, ग्राम सखौली निवासी रजमनिया पति रामदास घरेलू काम करके अपने 14 वर्षीय पुत्र आदित्य दास के साथ रहती हैं। 11 नवम्बर की शाम करीब 06.30 बजे वह घर के दरवाजे में बाहर से ताला बंद करके अपने भाई आनंद दास के घर खाना खाने गई थी और वहीं रात में सो गई थी।

आज खर्रा नदी में घाट बंधान के साथ हुई छठ पूजा की शुरुआत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



घुनघुट्टा श्याम सेवा समिति सोहगा करजी द्वारा खर्रा नदी पर छठ पूजा मानते लगभग 25 वर्ष हो गये। समिति के संरक्षक राकेश गुप्ता ने बताया कि छठ पूजा की शुरुवात गांव के महज कुछ लोग खर्रा नदी पर सन 2000 में हुई। उस समय छठ पूजा का प्रचलन और आवागमन के सीमित साधन होने कारण भीड़ कम होती थी । वर्ष 2015 से समिति ने घाट की साफ सफाई से लेकर अन्य जरूरी सुबिधा पर ध्यान दिया। अम्बिकापुर में छठ पूजा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और शहर के आसपास घाट और पार्किंग की समस्या के बीच शहरवासियों को खर्रा नदी का घाट काफी पसंद आया। समिति पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 40000 श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। बेहतर को बेहतरीन करने का प्रयास आज भी जारी है आज घुनघुट्टा श्याम सेवा समिति सोहगा-करजी के द्वारा छठ पूजा की शुरुवात विधिवत घाट पूजा के साथ हुई। समिति के संरक्षक राकेश गुप्ता स्वयं भी सपरिवार छठ ब्रत कर रहे हैं। उन्होंने पुनः सभी छठ ब्रती माताओं-बहनों और श्रद्धालुओं से छठ पूजा में शामिल होने का आग्रह किया है।

अनजान कॉल रिसीव करने के बाद खाते से 98 हजार गायब हुआ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कोतवाली थाना क्षेत्र के घुटरापारा निवासी एक महिला के खाते से 98 हजार रुपये अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पार कर देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक,शांतनु गुप्ता पिता प्रमोद गुप्ता 18 वर्ष, निवासी घुटरापारा ने लिखित आवेदन देकर बताया है कि उसकी मां सीमा गुप्ता' का बैंक ऑफ इंडिया में खाता है,जो मोबाइल नंबर से लिंक है। 06 नवम्बर को अनजान नम्बर से उसकी मां के नंबर पर कॉल आया। शांतनु ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर वह फोन काट दिया। कुछ दिन बाद जब वह खाते का स्टेटमेंट चेक किया तो पता चला कि उसी दिन यूपीआई के जरिए 98 हजार रुपये कट गए हैं। युवक ने इसकी जानकारी अपनी मां को देने के बाद कोतवाली थाना पुलिस को लिखित में ठगी की घटना से अवगत कराया है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल,कटघोरा (छ.ग.)

कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत कसनिया डिपों में होने वाले ई-नीलाम के लिये प्रस्तावित जांजगीर चाम्पा वनमण्डल के विभिन्न डिपो में रखे गये वनोपज के नीलाम हेतु मात्रा की जानकारी ।

नीलाम दिनांक 19.11.2026

अ.क्र.	डिपो का नाम	प्रजाति	पिछले नीलाम का शेष							नया वनोपज							योग						
			लट्ठा		बल्ली / डेंगरी		जलाऊ	बांस		लट्ठा		बल्ली / डेंगरी		जलाऊ	बांस		लट्ठा		बल्ली / डेंगरी		जलाऊ	बांस	
			नग	घ.मी	नग	घ.मी	चट्टा	नग	नो.टन	नग	घ.मी	नग	घ.मी	चट्टा	नग	नो.टन	नग	घ.मी	नग	घ.मी	चट्टा	नग	नो.टन
1	निस्तार डिपो सक्ती	अन्य	82	12.369	3	0.108											82	12.369	3	0.108	0	0	0
		सागौन	50	4.100		0.013				3	0.193						53	4.293	0	0.013	0	0	0
		साल			6	0.168											0	0.000	6	0.168	0	0	0
		अर्जुन								34	4.559						34	4.559	0	0.000	0	0	0
		कसही								2	0.200						2	0.200	0	0.000	0	0	0
		सतकठा					57										0	0.000	0	0.000	57	0	0
2	अकलतरा डिपो	सागौन	29	3.846	384	3.127											29	3.846	384	3.127	0	0	0
		नीलगिरी			739	8.671											0	0.000	739	8.671	0	0	0
		सतकठा															0	0.000	0	0.000	0	0	0
		आद्यो. बांस						70	0.044								0	0.000	0	0.000	0	70	0
		खैर								71	1.946			87			71	1.946	0	0.000	87	0	0
		तेंदू								783	21.857						783	21.857	0	0.000	0	0	0
3	जांजगीर	सागौन	16	0.943	4	0.046											16	0.943	4	0.046	0	0	0
		अन्य	184	26.511													184	26.511	0	0.000	0	0	0
		सतकठा					114										0	0.000	0	0.000	114	0	0
4	पंतोरा डिपो	तेंदू	130	20.861													130	20.861	0	0.000	0	0	0
		साजा	45	9.337													45	9.337	0	0.000	0	0	0
		अन्य	30	4.174													30	4.174	0	0.000	0	0	0
		हल्दू	6	1.059													6	1.059	0	0.000	0	0	0
		बीजा	4	0.572													4	0.572	0	0.000	0	0	0
		साल	39	6.045	6	0.027											39	6.045	6	0.027	0	0	0
		सागौन			6	0.101											0	0.000	6	0.101	0	0	0
		सतकठा					1										0	0.000	0	0.000	1	0	0
योग			615	89.817	1148	12.261	172	70	0.044	893	28.755	0	0.000	87	0	0.000	1508	118.572	1148	12.261	259	70	0.044

टीप -1. केता को ई-ऑक्सन के पूर्व MSTC E-commerce पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व कय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है, सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर 15 प्रतिशत E.M.D. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो MSTC E-commerce पोर्टल में अपने आई डी से लॉगईन करके देख सकते है।
4. ई- ऑक्शन में लॉट कय के पश्चात प्रथम केता को 40 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा, उसीलॉट में अन्य केताओं द्वारा 40 सेकण्ड पूर्व कय करने पर 30 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा ।

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल,कटघोरा

जी.नं.-262704508/2

CMYK

वीवीआईपी लोकार्पण के बाद 'गायब' हुआ पर्यटक वाहन!

गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में बड़े फर्जीवाड़े की बू, जांच की मांग तेज



तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था लोकार्पण (जून 2022, रामगढ़-कोरिया)



पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया गया था वाहन, अब इसकी मौजूदगी पर सवाल

- क्या वाहन सरकारी राशि से खरीदा गया था?
- या कार्यक्रम के लिए किराये पर लाया गया था?
- खरीदी/किराये का भुगतान किसे और कितना हुआ?
- वाहन किसके नाम पर पंजीकृत है?
- लोकार्पण के बाद कितने दिन तक चला?
- आज वाहन कहां हैं और किसके कब्जे में है?

बड़े सवाल?



कार्यालय, सहायक निदेशक गुरू घासीदास तमोर पिंगला टाईगर रिजर्व, बैकुंठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)
Phone No:-7470584593 E-mail: adggbkp49@gmail.com
क्रमांक/1427 बैकुंठपुर,दिनांक: 10/11/2026
प्रति,
पुष्पेन्द राजवाड़े
अध्यक्ष कोरिया जन सहयोग समिति
वार्ड क्र0 01,ग्राम–सोनहत
जिला–कोरिया (छ.ग.)
विषय :- जून 2022 के वीवीआईपी लोकार्पण के बाद से पर्यटक वाहन के गायब होने, प्रशासनिक अनियमितताओं, फर्जीवाड़े एवं फर्जी लोकार्पण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच 10 दिवस के भीतर कड़ी कार्यवाही बाबत।
संदर्भ :- संचालक कार्यालय का पत्र क्र0/शिकायत/2179 दिनांक 30.10.2026
—00—
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि, शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में आपके पास उपलब्ध समस्त दस्तावेज, अभिलेख, फोटो एवं अन्य साक्ष्य सहित इस कार्यालय में दिनांक 17.11.2026 को समय 03:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
सहायक निदेशक
गुरू घासीदास तमोर पिंगला टाईगर रिजर्व
बैकुंठपुर

» मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रभारी सचिव, कलेक्टर, एसपी, डीएफओ समेत कई बड़े अधिकारी थे मौजूद, फिर भी वाहन 'गायब' कैसे?

शिकायतकर्ता से ही मांगे जा रहे दस्तावेज, विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

लोकार्पण विभाग ने कराया, सबूत शिकायतकर्ता से मांग रहा विभाग!

शिकायत की तो सबूत भी आप ही लाओ! सरकारी जांच का नया तरीका

लोकार्पण की तस्वीरें सार्वजनिक, विभागीय रिकॉर्ड विभाग के पास, फिर शिकायतकर्ता के दरवाजे क्यों पहुंचा जांच का पत्र?

शिकायतकर्ता बनेगा जांच अधिकारी? वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल, सरकारी वाहन की शिकायत पर विभाग ने समिति अध्यक्ष को बुलाया, अपनी फाइलों की पड़ताल कितनी हुई?

फीता काटने में आगे, जवाबदेही में पीछे! वीवीआईपी लोकार्पण के बाद पर्यटक वाहन गायब होने का आरोप, अब शिकायतकर्ता से ही मांगे जा रहे दस्तावेज

वाहन किसने गायब किया, यह जांचेगा कौन? शिकायतकर्ता या वन विभाग! सरकारी संपत्ति का हिसाब मांगने पर समिति अध्यक्ष को तलब, विभागीय जवाबदेही पर बड़ा सवाल

वीवीआईपी उद्घाटन के बाद 'गायब' पर्यटक वाहन की जांच में वन विभाग का अजीब तरीका

मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारी थे लोकार्पण के गवाह, अपनी फाइलें खंगालने के बजाय समिति अध्यक्ष को दस्तावेज लेकर बुलाया

राजन पाण्डेय

बैकुंठपुर/सोनहत, 14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

लोकतंत्र में शिकायत करना नागरिक का अधिकार है और शिकायत पर निष्पक्ष जांच करना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि किसी सरकारी अनियमितता की शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता को ही दस्तावेज जुटाने, साक्ष्य तलाशने और तस्वीरें लेकर कार्यालय पहुंचने के निर्देश मिलने लगें, तो सवाल केवल एक शिकायत तक सीमित नहीं रहता, सवाल पूरी शिकायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो जाता है, क्या अब सरकारी विभागों में शिकायत करना ही शिकायतकर्ता के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है? क्या सरकारी रिकॉर्ड की जांच करने के बजाय शिकायतकर्ता से ही कहा जाएगा कि पहले आप प्रमाण लेकर आइए, फिर आपकी शिकायत पर विचार होगा? और यदि शिकायतकर्ता के पास ही सभी दस्तावेज, अभिलेख और साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो फिर विभागीय जांच की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से जुड़े कथित पर्यटक वाहन का मामला इन सवालों को बेहद गंभीरता से सामने ला रहा है, जून 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ में एक पर्यटक वाहन का लोकार्पण कराया गया था। कार्यक्रम में तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रभारी सचिव एस.प्रकाश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी की जानकारी सामने आई थी, वाहन पर बाकायदा 'पर्यटक वाहन ईको विकास समिति लोलकी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान' अंकित था।

अब कोरिया जन सहयोग समिति ने इसी वाहन की वर्तमान स्थिति, खरीद अथवा किराये, भुगतान, पंजीयन, संचालन और सुपुर्दगी को लेकर सवाल उठाए हैं, समिति ने आरोप लगाया है कि लोकार्पण के बाद वाहन का पता नहीं चल रहा है, इसी संबंध में उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई, लेकिन शिकायत के बाद वन विभाग की ओर से जो पत्र जारी हुआ, उसने एक नई बहस छेड़ दी है, सहायक संचालक कार्यालय ने 10 नवंबर 2026 को समिति अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े को पत्र जारी कर 17 नवंबर को दोपहर 3 बजे संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज, अभिलेख, फोटो और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, अब सवाल यह है कि जिस वाहन का लोकार्पण वन विभाग ने कराया, जिस आयोजन में शासन-प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिस सुविधा को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया, उसकी मूल फाइलें और रिकॉर्ड तलाशने की पहली जिम्मेदारी किसकी है? शिकायतकर्ता की या संबंधित विभाग की? सरकारी वाहन का लोकार्पण विभाग ने कराया, लेकिन अब उसका हिसाब मांगने वाला शिकायतकर्ता ही दस्तावेज लेकर आएगा! यही वह विडंबना है, जिसने इस मामले को और गंभीर बना दिया है।

शिकायत में लिखे तथ्य क्या जांच के योग्य नहीं?

कोरिया जन सहयोग समिति ने अपनी शिकायत में कई सीधे और स्पष्ट सवाल उठाए हैं, वाहन खरीदा गया था या किराये पर लिया गया था? यदि खरीदा गया था तो किस मद से राशि जारी हुई? बिल कहां है? पंजीयन प्रमाणपत्र कहां है? वाहन किसके नाम पर दर्ज है? यदि किराये पर लिया गया था तो भुगतान किसे किया गया? लोकार्पण के बाद वाहन किसे सौंपा गया? वर्तमान में वह कहां है? ये सवाल किसी अनुमान या अफवाह पर आधारित निष्कर्ष नहीं हैं, बल्कि ऐसे बिंदु हैं जिनकी पुष्टि सरकारी अभिलेखों से की जा सकती है, शिकायतकर्ता ने इन्हीं तथ्यों की जांच की मांग की है, ऐसे में जांच का पहला कदम क्या होना चाहिए? संबंधित विभाग की खरीद फाइल देखना, भुगतान रिकॉर्ड खंगालना, स्टॉक रजिस्टर का परीक्षण करना, वाहन का पंजीयन सत्यापित करना और उसकी वर्तमान भौतिक स्थिति का पता लगाना, लेकिन विभागीय पत्र में शिकायतकर्ता को ही दस्तावेज, अभिलेख और तस्वीरें लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, यहां एक बुनियादी सवाल है की क्या शिकायत में लिखे तथ्य जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं? यह सही है कि शिकायत में लगाए गए आरोप अपने आप में प्रमाणित तथ्य नहीं होते, जांच के बाद ही उनकी पुष्टि या खंडन किया जा सकता है, लेकिन शिकायत में लिखे तथ्यों की जांच करना तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है, शिकायतकर्ता से उपलब्ध साक्ष्य मांगना जांच का एक हिस्सा हो सकता है, मगर सरकारी रिकॉर्ड की जांच का विकल्प नहीं, यदि शिकायतकर्ता के पास ही सभी दस्तावेज और अभिलेख उपलब्ध होते, तो उसे विभाग से जांच कराने की जरूरत ही क्यों पड़ती? क्या शिकायतकर्ता सरकारी खरीद अधिकारी है? क्या वही भुगतान की फाइल रखता है? क्या वही स्टॉक रजिस्टर का प्रभारी है? क्या उसी के पास वाहन की सरकारी लॉगबुक और ईंधन खर्च का रिकॉर्ड होना चाहिए? सरकारी रिकॉर्ड सरकारी कार्यालय में होना चाहिए, शिकायतकर्ता की जेब में नहीं।

लोकार्पण सार्वजनिक, तस्वीरें सार्वजनिक, फिर सबूत के लिए शिकायतकर्ता ही क्यों?- इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कथित पर्यटक वाहन का लोकार्पण किसी बंद कमरे में नहीं हुआ था, यह एक सार्वजनिक और वीवीआईपी आयोजन था, तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रभारी सचिव और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक तथा वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वाहन को पर्यटन सुविधा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यदि वाहन उस समय मौजूद था, तो उसका लोकार्पण कार्यक्रम की तस्वीरों और वीडियो में दिखाई देना चाहिए, आयोजन से संबंधित विभागीय समाचार, जनसंपर्क सामग्री, कार्यक्रम विवरण और अन्य अभिलेख भी उपलब्ध होने चाहिए, ऐसे में जांच अधिकारी के सामने सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए कि विभाग अपने रिकॉर्ड से लोकार्पण की पुष्टि क्यों नहीं करता? वाहन किस उद्देश्य से लाया गया था? किस मद से व्यवस्था की गई थी? किस अधिकारी ने स्वीकृति दी थी? कार्यक्रम के बाद वाहन किसे सौंपा गया? यदि तस्वीरों में वाहन मौजूद है तो वह वाहन की उस समय की मौजूदगी का प्रमाण हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाहन कहां गया, किसने चलाया, किसके कब्जे में रहा और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है–इसका जवाब विभागीय रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन से ही मिलेगा, तस्वीरें सार्वजनिक हैं, लोकार्पण सार्वजनिक था, अधिकारी सार्वजनिक मंच पर मौजूद थे, फिर जांच की शुरुआत विभागीय फाइलों से क्यों नहीं? यहां यह भी समझना जरूरी है कि लोकार्पण की तस्वीर अपने आप में वाहन की खरीद, भुगतान या बाद के संचालन का प्रमाण नहीं है, इन पहलुओं की पुष्टि के लिए खरीद फाइल, भुगतान अभिलेख, पंजीयन और लॉगबुक की जांच जरूरी है, लेकिन यही तो जांच अधिकारी का काम है।

जांच अधिकारी का काम शिकायतकर्ता का कथन लेना भर नहीं- किसी शिकायत की निष्पक्ष जांच में शिकायतकर्ता का पक्ष सुनना महत्वपूर्ण है, उससे यह जानना जरूरी हो सकता है कि उसे जानकारी कहां से मिली, उसके पास कौन-से दस्तावेज हैं और वह किन तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन जांच का दायरा यहीं समाप्त नहीं हो सकता, यदि शिकायत सरकारी वाहन की खरीद और उसके गायब होने से जुड़ी है, तो जांच अधिकारी को संबंधित विभाग की खरीद फाइल, स्वीकृति आदेश, बिल-वाउचर, भुगतान विवरण, पंजीयन, स्टॉक रजिस्टर, सुपुर्दगी पत्र और वाहन के भौतिक सत्यापन की जांच करनी होगी, यदि वाहन किराये पर लिया गया था, तो किराया अनुबंध, भुगतान और वाहन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी का विवरण खंगालना होगा, यदि वाहन ईको विकास समिति को सौंपा गया था, तो हस्तांतरण और संचालन के अभिलेख देखने होंगे, यदि वाहन पर्यटन के लिए संचालित हुआ था, तो लॉगबुक, ईंधन खपत, चालक का विवरण और आय-व्यय का रिकॉर्ड जांचना होगा, यानी जांच का असली काम सरकारी रिकॉर्ड की कड़ियों को जोड़ना है, शिकायतकर्ता का कथन लेना जरूरी हो सकता है, लेकिन केवल कथन लेकर या उससे दस्तावेज लेकर जांच पूरी नहीं मानी जा सकती, क्या अब नागरिक शिकायत करेगा, दस्तावेज जुटाएगा, गवाह तलाशेगा, विभागीय फाइलें खोजेगा और जांच की दिशा भी खुद ही बताएगा? यदि ऐसा ही होना है तो सरकारी जांच व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

विभाग के अपने पत्र में दर्ज है कि जांच चल रही है- 10 नवंबर 2026 को जारी सहायक संचालक कार्यालय के पत्र क्रमांक 1427 में संचालक कार्यालय के पत्र क्रमांक शिकायत/2179, दिनांक 30 अक्टूबर 2026 का संदर्भ दिया गया है, पत्र के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जून 2022 के वीवीआईपी लोकार्पण के बाद पर्यटक वाहन के गायब होने, प्रशासनिक अनियमितताओं, फर्जीवाड़े एवं फर्जी लोकार्पण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच और 10 दिनों के भीतर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी, पत्र में कहा गया है कि शिकायत के संबंध में कार्यालय में जांच कार्रवाई की जा रही है, इसी क्रम में शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज, अभिलेख, फोटो एवं अन्य साक्ष्य लेकर 17 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके, इसका अर्थ है कि विभाग ने शिकायत को जांच के लिए लिया है, लेकिन अभी तक इस पत्र में किसी आरोप की पुष्टि, किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने या किसी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का उल्लेख नहीं है, अब असली परीक्षा यह होगी कि जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से मिले साक्ष्यों के साथ विभागीय रिकॉर्ड का भी परीक्षण करता है या नहीं।

पत्र की प्रतिलिपि उप संचालक को भी—यही है जांच की असली कसौटी- इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सहायक संचालक ने अपने पत्र की प्रतिलिपि उप संचालक, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भी भेजी है, इसमें उप संचालक कार्यालय में उपलब्ध संबंधित अभिलेख जांच अधिकारी को समय पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि वस्तुस्थिति की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके, यह निर्देश महत्वपूर्ण है, इससे स्पष्ट है कि जांच में विभागीय अभिलेखों की भूमिका भी स्वीकार की गई है, अब देखना यह होगा कि संबंधित कार्यालय कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करता है और उनकी शिकायत में उठाए गए सवालों से किस तरह तुलना की जाती है, यहां विभाग के पास भी जवाब देने का अवसर है। यदि वाहन खरीदा गया था तो खरीद की फाइल प्रस्तुत की जाए, यदि किराये पर लिया गया था तो अनुबंध और भुगतान का विवरण सामने रखा जाए, यदि समिति को सौंपा गया था तो हस्तांतरण पत्र दिखाया जाए, यदि वाहन संचालित हुआ था तो लॉगबुक और ईंधन खर्च का रिकॉर्ड पेश किया जाए, शिकायतकर्ता से साक्ष्य मांगना एक बात है, लेकिन विभाग के अपने अभिलेखों की पड़ताल करना जांच की अनिवार्य जिम्मेदारी है।

वाहन खरीदा गया था तो खरीद की कुंडली खोलिए- इस पूरे प्रकरण में पहला सवाल वाहन के स्वामित्व और खरीद प्रक्रिया का है, यदि वाहन सरकारी राशि से खरीदा गया था, तो उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति किसने दी? राशि किस मद से जारी हुई? वाहन किस कंपनी या एजेंसी से खरीदा गया? क्या निर्धारित खरीद प्रक्रिया अपनाई गई? बिल किसके नाम पर बना? भुगतान किस खाते से हुआ? वाहन किसके नाम पर पंजीकृत हुआ? इसके साथ ही वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि भी सामने आनी चाहिए, यदि रिकॉर्ड में वाहन विभागीय संपत्ति के रूप में दर्ज है तो उसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए, यदि वाहन किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित किया गया था तो हस्तांतरण आदेश और प्राप्ति दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए, यदि वाहन रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन मौके पर नहीं मिलता, तो यह जांच का गंभीर विषय होगा।

किराये का वाहन था तो भुगतान किसे हुआ?- दूसरी संभावना यह है कि वाहन खरीदने के बजाय किसी निजी एजेंसी या व्यक्ति से किराये पर लिया गया हो, यदि ऐसा था तो विभाग को बताना होगा कि वाहन किससे लिया गया, कितने समय के लिए लिया गया, किराया कितना तय हुआ और भुगतान किस मद से किया गया, क्या इसके लिए अनुबंध बनाया गया था? क्या वाहन केवल वीवीआईपी कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया गया था? क्या कार्यक्रम के बाद उसे वापस कर दिया गया? यदि वाहन को पर्यटक सुविधा के रूप में प्रस्तुत किया गया था तो उसके पीछे विभागीय व्यवस्था क्या थी? खरीद और किराये की दोनों स्थितियों में भुगतान और स्वीकृति के दस्तावेज होने चाहिए, वाहन खरीदा गया हो या किराये पर आया हो, दोनों ही रास्ते आखिरकार सरकारी फाइल तक पहुंचते हैं।

ईको विकास समिति लोलकी को सौंपा गया था तो सुपुर्दगी पत्र कहां है?- वाहन पर ईको विकास समिति लोलकी का नाम अंकित होने की जानकारी के बाद समिति की भूमिका भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यदि वाहन संचालन के लिए समिति को सौंपा गया था तो उसका लिखित आदेश कहां है? क्या समिति को वाहन की चाबी, पंजीयन दस्तावेज और अन्य कागजात सौंपे गए थे? वाहन चलाने के लिए चालक किसने नियुक्त किया? उसके भुगतान का हिसाब किसके पास है? क्या पर्यटकों को वाहन से पर्यटन स्थलों तक ले जाया गया? यदि हां, तो कितने पर्यटकों ने इस सुविधा का उपयोग किया? क्या उनसे शुल्क लिया गया? क्या वह राशि समिति के बैंक खाते में जमा हुई? वाहन के ईंधन, मरम्मत और रखरखाव का खर्च किसने उठाया? क्या समिति की बैठकों में वाहन संचालन का विवरण रखा गया? इन सवालों का जवाब समिति के पास उपलब्ध दस्तावेजों और विभागीय अभिलेखों के मिलान से ही सामने आ सकता है।

शिकायत प्रणाली का भरोसा टूटेगा तो अनियमितताओं पर सवाल कौन उठाएगा?- इस प्रकरण का सबसे गंभीर पहलू केवल एक पर्यटक वाहन नहीं है, यह सरकारी शिकायत व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है, जब कोई नागरिक या सामाजिक संगठन किसी अनियमितता को देखकर शिकायत करता है, तो वह उम्मीद करता है कि विभाग उसकी शिकायत पर ध्यान देगा, लेकिन यदि शिकायत के बाद उसे ही दस्तावेज जुटाने, तस्वीरें लाने और प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए बार-बार कार्यालय जाना पड़े, तो स्वाभाविक है कि वह निराश होगा, धीरे-धीरे ऐसी स्थिति बन सकती है कि लोग शिकायत करने से पहले ही सोचने लगें– शिकायत करके क्या हासिल होगा? समय और मेहनत अलग लगेगी, सरकारी कार्यालयों के चक्कर अलग लगाने पड़ेंगे और अंत में दस्तावेज भी खुद ही जुटाने होंगे, यह किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही जैसे मामलों में नागरिकों की शिकायतें प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण सूचना होती हैं, कई बार विभागीय स्तर पर जिन कमियों पर ध्यान नहीं जाता, वे शिकायतों के माध्यम से सामने आती हैं, यदि शिकायतकर्ता को ही सबूत जुटाने के नाम पर उलझा दिया जाएगा, तो शिकायत व्यवस्था धीरे-धीरे औपचारिकता बनकर रह सकती है, शिकायतें कम होने का अर्थ यह नहीं होगा कि अनियमितताएं समाप्त हो गईं, यह भी हो सकता है कि लोग शिकायत करना ही छोड़ दें।

वर्तमान सरकार में जवाबदेही की व्यवस्था पर गंभीर सवाल- सरकारें बदलती हैं, लेकिन जनता की अपेक्षाएं नहीं बदलतीं, नागरिक किसी भी सरकार में हों, उन्हें अपनी शिकायत पर निष्पक्ष जांच और समयबद्ध कार्रवाई की उम्मीद रहती है, वर्तमान सरकार के दौर में प्रशासनिक जवाबदेही और शिकायतों के निपटारे की कार्यप्रणाली को लेकर इस तरह के सवाल उठना गंभीर चिंता का विषय है, सरकार का दायित्व केवल योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास और लोकार्पण तक सीमित नहीं होता, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, उसके उपयोग का हिसाब और सार्वजनिक धन की जवाबदेही भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है, यदि किसी विभाग के अधिकारी शिकायतकर्ता से दस्तावेज मांगते हैं तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि विभाग ने अपने स्तर पर अब तक कौन-कौन से रिकॉर्ड जांचे हैं, क्या वाहन की खरीद फाइल देखी गई? क्या भुगतान का विवरण निकाला गया? क्या स्टॉक रजिस्टर की जांच हुई? क्या वाहन के पंजीयन की जानकारी प्राप्त की गई? क्या वर्तमान भौतिक सत्यापन कराया गया? क्या लोकार्पण कार्यक्रम की तस्वीरें और विभागीय समाचार रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं? इन सवालों के जवाब के बिना केवल शिकायतकर्ता को बुला लेना जांच की पूरी प्रक्रिया नहीं हो सकती, शिकायतकर्ता व्यवस्था का विरोधी नहीं होता। वह व्यवस्था को सूचना देता है, उसकी शिकायत को व्यक्तिगत विवाद की तरह देखने के बजाय तथ्यों की कसौटी पर परखना चाहिए।

17 नवंबर को सिर्फ शिकायतकर्ता नहीं, विभाग की जवाबदेही भी परखी जाएगी- अब 17 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक इस मामले का महत्वपूर्ण पड़ाव होगी, समिति अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े को अपने पास उपलब्ध दस्तावेज, जानकारी और तस्वीरें प्रस्तुत करनी हैं, लेकिन यह बैठक केवल शिकायतकर्ता के साक्ष्य लेने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, विभाग को भी अपने मूल अभिलेख सामने रखने चाहिए, कोरिया जन सहयोग समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े, कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता जयचंद सोनपाकर और अन्य पदाधिकारियों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, समिति पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो वह न्यायालय की शरण लेगी, अब विभाग को स्पष्ट करना होगा कि उसने अपने स्तर पर कौन-कौन से दस्तावेज जांचे हैं और वाहन की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं।







खदानें चलाने में नाकाम SECL प्रबंधन,बंद करने और फिर खोलने के खेल में उलझा करोड़ों का सरकारी संसाधन!

पर्यावरणीय अनुमति के अभाव में कटकोना 1×2 खदान बंद, 555 कर्मचारियों का वेतन जारी

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने,ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और सरकारी उपक्रमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के दावे किए जाते हैं,केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं,साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भी इसी व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है,लेकिन कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में SECL की खदानों की मौजूदा स्थिति इन दावों और जमीनी प्रबंधन के बीच एक बड़ा विरोधाभास उजागर कर रही है,यहां एक तरफ वर्षों से संचालित कटकोना 1×2 खदान पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में 1 नवंबर 2026 से बंद बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ वर्ष 2017 में बंद कर दी गई कटकोना 3×4 खदान को दोबारा शुरू करने के लिए टेंडर और विकास कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकारी कंपनी के पास खनन विशेषज्ञों,पर्यावरण अधिकारियों,तकनीकी कर्मचारियों और प्रशासनिक संसाधनों की पूरी व्यवस्था है, उसकी एक चालू खदान आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति के अभाव में उत्पादन क्यों नहीं कर पा रही है? क्या प्रबंधन को अनुमति समाप्त होने की जानकारी नहीं थी? क्या नवीनीकरण की प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हुई? या फिर वर्षों से लंबित पर्यावरणीय और वन स्वीकृति से जुड़े मामलों का प्रभावी समाधान निकालने में अधिकारी असफल रहे? मामला केवल एक खदान के बंद होने तक सीमित नहीं है,इससे कंपनी के उत्पादन,राजस्व, कर्मचारियों की कार्यक्षमता,मशीनरी के उपयोग और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण पर भी सवाल उठ रहे हैं,उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार खदान में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्टाफ सहित लगभग 555 लोग कार्यरत हैं, इनका प्रतिदिन का वेतन का लगभग भार करीब 16 लाख 65 हजार रुपये बताया जा रहा है,इस हिसाब से 13 दिनों में लगभग 2 करोड़ 16 लाख 45 हजार रुपये का वेतन भार बनता है, उत्पादन बंद है,लेकिन वेतन और अन्य स्थायी खर्चों का सिलसिला जारी है, यह स्थिति उस सरकारी उपक्रम की है, जिसके लिए कोयला उत्पादन और संसाधनों का अधिकतम उपयोग प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए,ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर स्थानीय बैकुंठपुर क्षेत्र का प्रबंधन अपनी चालू खदान को निर्बाध रूप से संचालित रखने की तैयारी क्यों नहीं कर पाया?

1974 से संचालित खदान को आज पर्यावरणीय अनुमति का इंतजार,यह कैसी प्रबंधन व्यवस्था?-

कटकोना 1×2 खदान का इतिहास लगभग पांच दशक पुराना बताया जाता है,वर्ष 1974 से संचालित इस खदान ने क्षेत्र में कोयला उत्पादन के साथ रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में भी योगदान दिया है,इतने लंबे समय से संचालित खदान के लिए पर्यावरणीय अनुमति और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया कोई नई व्यवस्था नहीं है,पर्यावरणीय स्वीकृति,वन स्वीकृति,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति और अन्य वैधानिक शर्तों का पालन खदान प्रबंधन की नियमित जिम्मेदारी होती है, सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि कटकोना भूमिगत कोयला खदान की उत्पादन क्षमता 0.225 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.36 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने के लिए 20 जून 2006 को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी,इस परियोजना का क्षेत्रफल 1130.929 हेक्टेयर दर्ज था,इसके बाद पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्वैधीकरण का मामला सामने आया, SECL ने 8 सितंबर 2018 को PARIVESH पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किया था, यह आवेदन निर्धारित छह महीने की समयसीमा के भीतर किया गया था, लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया में अतिरिक्त जानकारियां और दस्तावेज मांगे गए तथा मामला आगे बढ़ने के बजाय लंबित होता चला गया, यही वह बिंदु है जहां प्रबंधन की भूमिका की गंभीर समीक्षा आवश्यक हो जाती है,आवेदन समय पर किया गया था तो उसके बाद मांगी गई सभी जानकारियां और अनुपालन समय पर क्यों नहीं दिए गए? यदि वन स्वीकृति से संबंधित अड़चन थी तो उसके समाधान के लिए कंपनी ने कितनी तेजी से प्रयास किए? क्या संबंधित विभागों के साथ नियमित समन्वय किया गया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या खदान के संचालन पर संकट आने से पहले उच्चस्तरीय अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया था?

2018 से चल रही प्रक्रिया, 2025 तक भी क्यों नहीं निकला समाधान?-कटकोना खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति मामले का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 27वीं बैठक के कार्यवृत्त में सामने आता है, 18-19 जून 2025 की बैठक में कटकोना भूमिगत कोयला खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति पुनर्वैधीकरण का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया था,समिति के सामने बताया गया कि SECL ने 8 सितंबर 2018 को ही पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन कर दिया था,26 अक्टूबर 2018 की 40वीं EAC बैठक में अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने के कारण प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था,इसके बाद परियोजना प्रबंधन ने 28 मार्च 2025 और 25 मई 2025 को अतिरिक्त जानकारी PARIVESH पोर्टल पर प्रस्तुत की,यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है, जून 2025 की EAC बैठक में समिति ने पाया कि परियोजना क्षेत्र में कुल 1048.149 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है, जिसमें से 200.209 हेक्टेयर वन भूमि के लिए स्टेज-1 वन स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई थी,समिति ने स्पष्ट किया कि इस वन भूमि की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना पर्यावरणीय स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण नहीं किया जा सकता,इसी कारण प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाने के बजाय स्थगित कर दिया गया, यानी यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि SECL ने आवेदन ही समय पर नहीं किया था,आधिकारिक रिकॉर्ड बताता है कि आवेदन निर्धारित समय के भीतर किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि 2018 में शुरू हुई प्रक्रिया 2025 तक भी निर्णायक स्थिति में क्यों नहीं पहुंची? अतिरिक्त जानकारी और अनुपालन संबंधी कार्यवाही में इतना लंबा समय क्यों लगा? 200.209 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति के लिए आवेदन और समन्वय की प्रक्रिया किस स्तर पर अटकी रही? यहां SECL प्रबंधन के साथ-साथ संबंधित वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति से जुड़े विभागों की भूमिका भी जांच के दायरे में आती है।

2017 में बंद 3×4 खदान को दोबारा शुरू करने की तैयारी,पुराने फैसलों और करोड़ों के संसाधनों पर उठे सवाल

1974 से कोयला उगल रही कटकोना खदान आज अनुमति के लिए मोहताज! आखिर सोया रहा SECL प्रबंधन?

सरकारी कंपनी की खदान को पर्यावरणीय अनुमति नहीं! स्वष्टरुकी कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

एक खदान चलाने की अनुमति नहीं,दूसरी को दोबारा खोलने की तैयारी! SECL का कैसा खनन प्रबंधन?

कटकोना खदान बंद,उत्पादन शून्य और वेतन का बोझ जारी, SECL को रोजाना 16.65 लाख की देनदारी

2017 में चलती खदान बंद की, अब करोड़ों खर्च कर फिर खोलने की तैयारी,SECL के फैसलों पर सवाल

कटकोना में SECL का उलटफेर! करोड़ों की मशीनरी का हिसाब नहीं,चालू खदान भी बंद

अनुमति खत्म होने का इंतजार करता रहा SECL प्रबंधन? कटकोना खदान बंद होने से खुली लापरवाही की परतें

कोयले का ग्रेड गिरा, उत्पादन रुका और खर्च बढ़ा,कटकोना में SECL की दोहरी मार

200.209 हेक्टेयर वन भूमि बनी सबसे बड़ी अड़चन,पहले क्यों नहीं निकाला रास्ता?

EAC की बैठक के दस्तावेजों के अनुसार कटकोना परियोजना के अंतर्गत 1048.149 हेक्टेयर वन भूमि दर्ज है,इसमें 298 हेक्टेयर को पहले ही स्टेज-2 वन स्वीकृति मिल चुकी थी,जबकि 549.940 हेक्टेयर को स्टेज-1 वन स्वीकृति प्राप्त थी, शेष 200.209 हेक्टेयर के लिए नई वन स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही थी,समिति ने इसी 200.209 हेक्टेयर वन भूमि को लेकर आपत्ति दर्ज की और स्पष्ट किया कि आवश्यक स्टेज-1 वन स्वीकृति के बिना पर्यावरणीय स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण संभव नहीं है,यहां प्रबंधन से सीधा सवाल है कि जब खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति पुनर्वैधीकरण का मामला 2018 से चल रहा था तो वन भूमि से जुड़ी इस अड़चन का समाधान प्राथमिकता के आधार पर क्यों नहीं किया गया? क्या इस भूमि को परियोजना क्षेत्र से अलग करके शेष स्वीकृत क्षेत्र में संचालन की संभावना पर गंभीरता से विचार किया गया? क्या पर्यावरण मंत्रालय के सामने वैकल्पिक प्रस्ताव समय रहते प्रस्तुत किया गया? क्या संबंधित वन विभाग से उच्चस्तरीय समन्वय किया गया? यह भी उल्लेखनीय है कि EAC की बैठक में पहले की पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुपालन की प्रमाणित रिपोर्ट में कोई ऐसी शर्त नहीं बताई गई थी जिसे गैर-अनुपालित अथवा आंशिक रूप से अनुपालित दर्ज किया गया हो,इसके बावजूद वन स्वीकृति की कमी के कारण पुनर्वैधीकरण का मामला अटक गया,इसलिए यह मामला केवल पर्यावरणीय नियमों का नहीं,बल्कि कई विभागों के बीच लंबे समय से चल रही प्रशासनिक प्रक्रिया और उसके परिणामों का भी है।

555 कर्मचारियों का वेतन भार,उत्पादन बंद लेकिन खर्च जारी...

कटकोना 1×2 खदान में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्टाफ सहित लगभग 555 लोग कार्यरत बताए जा रहे हैं,उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनके वेतन पर प्रतिदिन करीब 16 लाख 65 हजार रुपये खर्च होते हैं। इस हिसाब से खदान बंद रहने के 13 दिनों में वेतन का कुल भार 2 करोड़ 16 लाख 45 हजार रुपये तक पहुंच गया है, वहीं 30 दिनों का वेतन भार लगभग 4 करोड़ 99 लाख 50 हजार रुपये और इसी दर से एक वर्ष का वेतन व्यय करीब 60.77 करोड़ रुपये बैठता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खदान से कोयले का उत्पादन बंद होने के बावजूद कर्मचारियों का वेतन और सुरक्षा,रखरखाव,बिजली तथा अन्य स्थायी खर्च जारी हैं, हालांकि नियमित कर्मचारियों का वेतन बंदी के कारण हुआ अतिरिक्त नुकसान नहीं माना जा सकता, लेकिन उत्पादन ठप रहने से कंपनी पर आर्थिक दबाव निश्चित रूप से बढ़ रहा है,इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन दिनों में नहीं हो पाए कोयला उत्पादन और उससे मिलने वाले संभावित राजस्व का है। यदि खदान की प्रतिदिन की वास्तविक उत्पादन क्षमता और कोयले की बिक्री दर को जोड़ा जाए तो बंदी से हुए आर्थिक नुकसान का वास्तविक आकलन सामने आ सकता है,ऐसे में स्वष्टरु प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि 13 दिनों की बंदी के दौरान कितना उत्पादन प्रभावित हुआ,कितने राजस्व का नुकसान हुआ और पर्यावरणीय अनुमति समय पर नहीं मिलने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?

10.28 करोड़ का मैन राइडिंग सिस्टम टेंडर,लेकिन परियोजना की पूरी तस्वीर क्या है?

कटकोना उपक्षेत्र में खदानों के विकास और भूमिगत आवागमन की सुविधा को लेकर मैन राइडिंग सिस्टम भी चर्चा में है, कोल इंडिया के ई-प्रोक्योरमेंट से जुड़े विवरण में कटकोना 1×2 और ढेलवाडीह सहित विभिन्न खदानों के लिए मैन राइडिंग सिस्टम की आपूर्ति एवं स्थापना से संबंधित संयुक्त टेंडर का उल्लेख सामने आया है,इसके अतिरिक्त कटकोना 3×4 के लिए अलग से चेयर लिफ्ट टाइप मैन राइडिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित टेंडर का विवरण भी उपलब्ध है, मैन राइडिंग सिस्टम भूमिगत खदानों में कर्मचारियों को लंबी दूरी तक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है,लेकिन इस पर होने वाला निवेश तभी उपयोगी होगा जब संबंधित खदान का संचालन और आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां सुनिश्चित हों, इसलिए प्रबंधन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कटकोना 3×4 के लिए कितनी लागत के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, किन एजेंसियों को काम मिला है, काम की समयसीमा क्या है और खदान को पुनः उत्पादन में लाने की वास्तविक तारीख क्या निर्धारित की गई है, साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कटकोना 1×2 के लिए आवश्यक मशीनरी और तकनीकी स्वीकृतियों की स्थिति क्या है।

दिलचस्प तथ्यः कटकोना 1×2 के मैन राइडिंग सिस्टम को मिल चुकी है सुरक्षा मंजूरी

खदान की मौजूदा स्थिति के बीच एक और महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज सामने आता है, खान सुरक्षा महानिदेशालय ने 29 जुलाई 2026 को कटकोना 1×2 भूमिगत खदान में स्थापित मैन राइडिंग चेयरलिफ्ट सिस्टम को पांच वर्ष के लिए नियमित मंजूरी दी थी, जिसकी वैधता 6 जून 2031 तक बताई गई है, इसका अर्थ है कि खदान में लगाए गए इस विशेष उपकरण के लिए सुरक्षा संबंधी नियमित स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की गई थी,लेकिन मैन राइडिंग सिस्टम की मंजूरी और पर्यावरणीय स्वीकृति दो अलग-अलग वैधानिक विषय हैं,एक की मंजूरी मिलने से दूसरी की आवश्यकता समाप्त नहीं होती, यही इस पूरे मामले का विरोधाभास है,खदान में तकनीकी व्यवस्था और सुरक्षा उपकरणों की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है,लेकिन पर्यावरणीय स्वीकृति का मामला लंबित रहने पर उत्पादन ठप्प हो सकता है,ऐसे में सवाल यह है कि प्रबंधन ने पर्यावरणीय अनुमति की प्रक्रिया को भी उसी गंभीरता और समयबद्धता से क्यों नहीं संभाला?

कोयले का ग्रेड जी3 से जी4,गुणवत्ता और राजस्व दोनों पर निगाह जरूरी

कटकोना 1×2 खदान में कोयले की गुणवत्ता और ग्रेड को लेकर भी चिंता जताई जा रही है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहले यहां उत्पादित कोयले का ग्रेड बेहतर श्रेणी में था, इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से जी3 और 1 अक्टूबर 2026 से जी4 ग्रेड दर्ज होने की बात कही जा रही है,कोयले का ग्रेड उसकी गुणवत्ता और ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू से जुड़ा होता है,सामान्य नॉन-कोकिंग कोयले में जी3 की कैलोरिफिक वैल्यू 6400 से 6700 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम तथा जी4 की 6100 से 6400 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के बीच होती है, इसका अर्थ है कि जी3 से जी4 में बदलाव होने पर कोयले की निर्धारित गुणवत्ता श्रेणी में गिरावट आती है,हालांकि वास्तविक मूल्य पर बिक्री चैनल,मूल्य अधिसूचना, कोयले के नमूने और अन्य व्यावसायिक शर्तों का भी प्रभाव पड़ता है,उपलब्ध स्थानीय जानकारी में जी3 का मूल्य 3420 रुपये प्रति टन और जी4 का 3250 रुपये प्रति टन बताया जा रहा है,प्रबंधन को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कोयले की गुणवत्ता में बदलाव के पीछे भूगर्भीय कारण हैं या उत्पादन के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण की कोई समस्या रही है,क्या संबंधित सीम में कोयले की प्राकृतिक गुणवत्ता बदल रही है? क्या अलग-अलग सीमों के कोयले का मिश्रण हो रहा है? क्या नमूनों की जांच और ग्रेड निर्धारण नियमित तरीके से किया जा रहा है? यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोयला उत्पादन में केवल टन के आंकड़े नहीं,बल्कि उसकी गुणवत्ता और बिक्री मूल्य भी कंपनी की आर्थिक स्थिति तय करते हैं।

निजी खदानों को लेकर सवाल,नियम समान तो सरकारी कंपनी क्यों पिछड़ रही?

इस पूरे मामले में एक व्यापक सवाल निजी और सरकारी खनन कंपनियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी उठ रहा है, पर्यावरणीय स्वीकृति के नियम सरकारी और निजी दोनों खदानों पर लागू होते हैं, किसी भी कंपनी को आवश्यक पर्यावरणीय और अन्य वैधानिक स्वीकृतियों के बिना खदान संचालित करने की छूट नहीं है,लेकिन जब सरकारी SECL की खदान पर्यावरणीय अनुमति के अभाव में बंद होती है और दूसरी तरफ निजी खनन परियोजनाएं अपनी स्वीकृति प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती हैं,तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर स्वष्टरुके प्रशासनिक तंत्र में ऐसी कौन-सी बाधा है,जो समय पर अनुमति प्राप्त करने में परेशानी पैदा कर रही है? क्या निजी कंपनियों के पास परियोजना प्रबंधन और पर्यावरणीय अनुपालन की बेहतर व्यवस्था है? क्या SECLमें निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक जटिल है? क्या संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव है? या फिर सरकारी उपक्रमों में जवाबदेही तय करने की व्यवस्था कमजोर पड़ रही है? इस तुलना का जवाब आंकड़ों और स्वीकृति रिकॉर्ड के आधार पर ही मिल सकता है,लेकिन इतना तय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते SECL की जिम्मेदारी कम नहीं, बल्कि अधिक है,क्योंकि यहां नुकसान केवल कंपनी का नहीं,बल्कि सार्वजनिक संसाधनों और सरकारी राजस्व का भी है।

खबर के सबसे मजबूत दस्तावेजी आधार

1. **20 जून 2006 - कटकोना की पर्यावरणीय स्वीकृति :** क्षमता 0.36 MTPA,परियोजना क्षेत्र 1130.929 हेक्टेयर और स्वीकृति की शर्तें। भारत सरकार का मूल पर्यावरणीय आदेश
2. **18-19 जून 2025 - EAC की 27वीं बैठक :** आवेदन की तारीख 8 सितंबर 2018, अतिरिक्त जानकारी की तारीखें,200.209 हेक्टेयर वन भूमि की बाधा और प्रस्ताव स्थगित करने का निर्णय। EAC की आधिकारिक बैठक कार्यवाही
3. **29 जुलाई 2026 - मैन राइडिंग सिस्टम की मंजूरी** कटकोना 1×2 के चेयरलिफ्ट सिस्टम को DGMS की पांच साल की नियमित स्वीकृति। DGMS का आधिकारिक स्वीकृति आदेश
4. **कोयले के ग्रेड का आधिकारिक वर्गीकरण :** जी3 और जी4 की GCV सीमा तथा कोयला ग्रेड निर्धारण का आधार। कोयला मंत्रालय की ग्रेड सूची।

CMYK


छठ पूजा की
हार्दिक शुभकामनाएं
राकेश गुप्ता
संरक्षक
घुनघुट्टा श्याम सेवा समिति
सोहगा-करजी
अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)


छठ पर्व पर जन-जन को
हार्दिक शुभकामनाएं...
गजेंद्र नारायण सिंह
श्रीमती मुखरानी देवी
जी.एन.सेवा समिति अम्बिकापुर


छठ पूजा की
हार्दिक
शुभकामनाएं
मनोज गुप्ता
पार्षद
वार्ड क्रमांक – 12, नमनाकला
अंबिकापुर (छ.ग.)


आस्था की डोर, विश्वास का
साथ, सूर्यदेव का आशीर्वाद
और छठी मैया का प्यार.
आपके जीवन में हमेशा बना
रहे खुशियों का संसार.
छठ पूजा 2026 की
हार्दिक शुभकामनाएं.


छठ पूजा की
हार्दिक
शुभकामनाएं
रविन्द्र तिवारी
संभागीय प्रभारी
आर्थिक प्रकोष्ठ
भारतीय जनता पार्टी, सरगुजा (छ.ग.)


समस्त सम्मानीय प्रदेशवासियों व सरगुजा क्षेत्रवासियों को
महापर्व सूर्यषष्ठी पर मंगलमय शुभकामनाएं...
लक्ष्मण साहू
श्रीमती फुलश्वरी साहू
ॐ भास्कराय पुत्रं देहि महादेजसे।
दीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्।।
जय हो सूर्य देव की
जय हो छठी मैया की
छठ पूजा की
हार्दिक शुभकामनाएं
संजय साहू
श्रीमती विमला साहू
नरशंकर साहू
श्रीमती पेंद्य साहू
रेपा
प्रिया
गौरव
सचिन
धर्मेन्द्र
प्रिंस
विनीत : श्याम कोल्ड स्टोरेज, बिलासपुर रोड, मणीपुर, अम्बिकापुर-सरगुजा (छ.ग.), मो. 7440670000





श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

जनजातीय गौरव दिवस

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर शत् शत् नमन

मुख्य अतिथि

श्री नितिन नवीन

माननीय राज्यसभा सांसद

15 नवंबर 2026

समय - प्रात: 9 बजे

दशहरा मैदान, धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

समावेशी विकास एवं उत्थान

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से **6,691** गांवों के **11 लाख** से अधिक परिवार और पीएम-जनमन से **1,544** गांवों के **56,569** परिवार लाभान्वित

संस्कृति और विरासत का संरक्षण

₹50 करोड़ की लागत से शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण



महिला सशक्तीकरण

19.89 लाख से अधिक जनजातीय महिलाओं को **₹629.64** करोड़ अंतरित मिल रहा **महतारी वंदन योजना** का लाभ

सुरक्षित भविष्य की आधारशिला

75 एकलव्य और **14 प्रयास** आवासीय विद्यालय संचालित, **34 हजार** से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित

सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन

9.86 लाख जनजातीय परिवारों को **पक्के आवास**

वन अधिकारों से सशक्तीकरण

4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत, **46,868** सामुदायिक और **4,412** सामुदायिक वन संसाधन **अधिकार पत्र वितरित**

समृद्धि । सम्मान । सर्वांगीण विकास

संवाद 49787/57

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)